कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

आवरण कथा : हैदराबाद बम धमाके

आतंकवाद पर 'राष्ट्रीय सहमति' समय की मांग
– **डॉ. शिव शक्ति बक्सी**..... 7

रिपोर्ट

वीवीआईपी हैलीकॉप्टर घोटाला
विकाश आनंद..... 12

साक्षात्कार

श्रीमती स्मृति ईरानी : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर विशेष..... 16

लेख

मार्कण्डेय काटजू को भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष पद से क्यों इस्तीफा दे देना चाहिए
–**अरुण जेटली**..... 10

कांग्रेस ने किया फतह भ्रष्टाचार का ऐवरेस्ट
–**अम्बा चरण वशिष्ठ**..... 14

देश की तरफ नजर उठाने वालों को कड़ा संदेश
–**चंदन मित्रा**..... 15

सेक्युलर तंत्र पर सवाल
– **बलबीर पुंज**..... 19

पं. दीनदयाल उपाध्याय : राजनीति में संस्कृति के राजदूत
–**ओमप्रकाश कोहली**..... 21

भाजपा के तीव्र विरोध के कारण शिन्दे को मांगनी पड़ी मुआफी
–**अम्बा चरण वशिष्ठ**..... 24

फिर घोटाले पर घोटाला!
–**परंजॉय गुहा ठाकुरता**..... 25

मुख्य पृष्ठ : *हैदराबाद बम धमाके स्थल का निरीक्षण करते श्री राजनाथ सिंह*

ऐतिहासिक चित्र

प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का आश्रम, वृन्दावन : श्री गुरुजी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी।

झूठ और सच

श्री गुरुजी की मान्यता थी कि यदि नयी पीढ़ी को अपने देश का गलत इतिहास पढ़ाया जाएगा, तो वे सदा भ्रमित ही रहेंगे। गलत बात को भी बार-बार सुनने से कैसे भ्रम उत्पन्न होते हैं, इस बारे में वे यह कथा सुनाते थे।

एक सरल स्वभाव के ग्रामीण ने बाजार से एक बकरी खरीदी। उसने सोचा था कि इस पर खर्च तो कुछ होगा नहीं, पर मेरे छोटे बच्चों को पीने के लिए दूध मिलने लगेगा। इसी सोच में खुशी-खुशी वह बकरी को कंधे पर लिये घर जा रहा था।

रास्ते में उसे तीन ठग मिल गये। उन्होंने उसे मूर्ख बनाकर बकरी हड़पने की योजना बनायी और उसके गाँव के रास्ते में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर खड़े हो गये। जब पहले ठग को वह ग्रामीण मिला, तो ठग बोला - भैया, इस कुतिया को क्यों पीठ पर उठाये ले जा रहे हो ?

ग्रामीण ने उसकी ओर उपेक्षा से देखकर कहा - अपनी आँखों का इलाज करा लो। यह कुतिया नहीं, बकरी है। इसे मैंने आज ही बाजार से खरीदा है। ठग हँसा और बोला - मेरी आँखें तो ठीक हैं, पर गड़बड़ तुम्हारी आँखों में लगती है। खैर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तुम जानो और तुम्हारी कुतिया।

ग्रामीण थोड़ी दूर और चला कि दूसरा ठग मिल गया। उसने भी यही बात कही - क्यों भाई, कुतिया को कंधे पर लादकर क्यों अपनी हँसी करा रहे हो। इसे फेंक क्यों नहीं देते ?

अब ग्रामीण के मन में संदेह पैदा हो गया। उसने बकरी को कंधे से उतारा और उलट-पलटकर देखा। पर वह थी तो बकरी ही। इसलिए वह फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा।

थोड़ी दूरी पर तीसरा ठग भी मिल गया। उसने बड़ी नम्रता से कहा - भाई, आप शक्ल-सूरत और कपड़ों से तो भले आदमी लगते हैं, फिर कंधे पर कुतिया क्यों लिये जा रहे हैं ? ग्रामीण को गुस्सा आ गया। वह बोला- तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जो इस बकरी को कुतिया बता रहे हो ? ठग बोला - तुम मुझे चाहे जो कहो, पर गाँव में जाने पर लोग जब हँसेंगे और तुम्हारा दिमाग खराब बतायेंगे, तो मुझे दोष मत देना।

जब एक के बाद एक तीन लोगों ने लगातार एक जैसी ही बात कही, तो ग्रामीण को भरोसा हो गया कि उसे किसी ने मूर्ख बनाकर यह कुतिया दे दी है। उसने बकरी को वहीं फेंक दिया। ठग तो इसी प्रतीक्षा में थे।

उन्होंने बकरी को उठाया और चलते बने।

यह कथा बताती है कि गलत बात को बार-बार बताने से बड़ा आदमी भी भ्रम में पड़ जाता है, तो फिर छोटे बच्चों की तो बात ही क्या है ? इसलिए बच्चों को शुरू से ठीक इतिहास पढ़ाया जाना आवश्यक है।

-'श्री गुरुजी बोधकथा' से साभार

स्वामी रामकृष्ण परमहंस जयंती (13 मार्च)

कमल संदेश परिवार की ओर से उन्हें नमन!

आपके हाथ में पद बांटना है पर बुद्धि.....!

यह कौन नहीं जानता कि कांग्रेस में 'न खाता न बही सोनिया जी जो कहे वो सही।' किसी जमाने में देवकांत बरूआ और सीताराम केसरी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, के बारे में मजाकिया कहावत के रूप में कहा जाता था, पर यह मजाकिया कहावत पिछले डेढ़ दशक से कहावत की धरातल का यथार्थ बन गया है। आरोप लगा कि पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल श्रीमती इंदिरा गांधी के घर खाना बनाती हैं। सही या गलत यह तो उनके घर के लोग जाने पर सूचनाओं को कौन रोक सकता है, हालांकि वर्तमान महामहिम के बारे में ऐसा तो नहीं कहा जा सकता पर हां, उनके द्वारा दिया गया पहले अभिभाषण ने लोगों को निराश किया और उनके 50 वर्षीय संसदीय अनुभव और संसद में बतौर कांग्रेस नेता की जो उनकी धार लोगों ने देखी थी वह अभिभाषण में कुंद थी। वैसे सोनिया जी ने जो-जो चाहा है इस समय वह-वह हो रहा है। इस समय राष्ट्रपति हों, लोकसभा अध्यक्ष हों, राज्यसभा सभापति हों, कांग्रेस संसदीय दल के नेता हों, गृहमंत्री हों या वित्तमंत्री या फिर विदेश या रक्षा मंत्री; इन पदों के नाम डॉ. मनमोहन सिंह नहीं, श्रीमती सोनिया गांधी तय करती है और उन्होंने ही तय किए हैं। और यह सब अधिकार उन्होंने अपने एक नाटकीय समर्पण से प्राप्त कर लिया। भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर नाम तय करने का अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया जिन्हें प्राचीन भारत का न इतिहास, न भूगोल और न ही संस्कृति का ज्ञान है। और जब किसी को भी ऐसा अधिकार मिल जाता है तो यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि पद पर कौन बैठ रहा है। महत्वपूर्ण यह होता है कि पद पर कौन बिठा रहा है? वर्तमान गृहमंत्री ऐसी ही व्यवस्थाओं से उत्पन्न हुए। माटी के गणेश जी की काबिलियत नहीं देखी गयी उन्हें अहसास कराया गया कि मैं प्रणब मुखर्जी जी को महामहिम बना सकती हूं और तुम्हें गृहमंत्री। सोनिया जी, यह सच है कि आज आप ऐसा कर सकती हैं पर सुशील कुमार शिंदे न सरदार वल्लभ भाई पटेल बन सकते हैं और न ही यशवंत राव चव्हाण। क्योंकि पद देना आपके हाथ में है पर प्रतिष्ठा! आज जो गृहमंत्री हैं वे अपने प्रारम्भिक जीवन में 'सब इंस्पेक्टर' थे। 'घटना घटी और एफआईआर लिखी' का कार्य करते थे। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई छोटा व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। पर यह तो देखना पड़ेगा कि किसे हम किस पद पर बिठा रहे हैं।

देश आंतरिक और बाह्य दोनों मोर्चों पर असहाय महसूस कर रहा है। सदन में गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यह कहा कि मैं 22 तारीख की प्रात: 3 बजे उठा। घटना स्थल पर सात बजे पहुंच गया तो इस बात की पुष्टि हो ही गई कि थानेदार को यदि आप गृहमंत्री बना दें तो उसका मूल स्वभाव नहीं बदलता है। भारत में गृहमंत्री की यह भाषा कभी नहीं हो सकती। जब वो अपना वक्तव्य सदन में पढ़ रहे थे तो लग रहा था थाने से रवानगी का चालान काट कर लाए हैं और उसी को पढ़ रहे हैं। भारत के गृहमंत्री से आगे भारत के अनेक न्यूज चैनल चल रहे थे। वे इस जानकारी तक पहुंच गए कि हैदराबाद ट्विन बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन है और भारत का दुर्भाग्य यह है कि उसका गृहमंत्री घटना की पुलिसिया जानकारी दे रहा है। सोनिया जी आपने शिंदे जी को पद दे दिया पर बुद्धि कौन देगा? दिक्कत यह है कि वह तो आपके पास अपने लायक भी नहीं है। पर मुझे यह कहने का अधिकार इसलिए नहीं है कि आपमें कुछ न कुछ तो है जिसके कारण 100 साल से पुरानी कांग्रेस की पतवार आपके हाथों में आपके कांग्रेसियों ने सौंपी है। गृहमंत्री का वक्तव्य स्वयं गृहमंत्री को चिढ़ा रहा था। लचर वक्तव्य में लाचार व्यक्तित्व की झलक स्वत: देखी जा सकती थी। भारत का गृहमंत्री मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। यह भारत ही है जहां मास्टर का बेटा श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री बनता है और मल्लाह नाविक का बेटा श्री एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है। पर आज तक किसी ने इनकी योग्यता और व्यक्तित्व

पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाए। अखबार बेचने से प्रारंभ की गयी जिंदगी 'मिसाइल मैन' बन जाता है। और छोटे से प्राथमिक स्कूल मास्टर का बेटा अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज यूएनओ में राष्ट्रभाषा में भाषण देकर तिरंगा को विश्व के नक्शे पर अपनी वाणी के जादू से फहराने का और लहराने का अहसास करा देता है। हमने कभी ऐसा मजाक नहीं सुना था कि लोग यह कहने लगे कि जिनका जमीनी आधार नहीं वे अब कांग्रेस के आधारपुरूष बन रहे हैं। डॉ. मनमोहन सिंह कभी चुनाव नहीं जीते। वे आज भी राज्यसभा के सदस्य हैं। वित्तमंत्री चिदम्बरम कैसे जीते यह किसी से छुपा नहीं है! ए.के. एंटोनी भी राज्यसभा के ही सदस्य हैं। कहा जाता है कि वह बहुत ईमानदार हैं लेकिन घोटलों की गाज जितनी रक्षा मंत्रालय पर गिर रही है शायद और किसी मंत्रालय पर नहीं गिर रही।

हैदराबाद के बम ब्लास्ट के पीछे की साजिश को यदि भारत सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया तो वह दिन दूर नहीं जब यूपीए सरकार ऐसी ही घटनाओं पर संवेदना और सहायता राशि बांटती रहेगी। यदि जयपुर में संपन्न हुए चिंतन शिविर में गृहमंत्री शिंदे द्वारा आतंकवाद पर दिए गए वक्तव्य पर यदि पाकिस्तान में जश्न मनाया जाता हो तो क्या ऐसे व्यक्ति को गृहमंत्री बने रहने का अधिकार है। हमने गृहमंत्री के हाथ में भारत की अस्मिता सौंपी है। और अस्मिता उसको सौंपी जाती है जिसे अस्मिता का ज्ञान होता है। जिसको एकता-अखंडता के प्रति अपने कर्त्तव्य का भाव सदैव बनाए रखना पड़ता है। गैर जिम्मेदाराना बयान देकर आतंकवादियों का हौसला-अफजाई करने वाले गृहमंत्री को क्या अपने पद पर बने रहना चाहिए? ■

दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे सरकार : राजनाथ सिंह

हैदराबाद में जो बम धमाकों की घटना घटी है वह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। हैदराबाद में हुए बम धमाकों में कई लोगों की जानें गई हैं एवं बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इस घटना में मारे गए लोगों के शोक संतृप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।

हैदराबाद में हुए ये बम धमाके आतंकवादियों के द्वारा देश को दी जाने वाली एक चुनौती हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस घटना की विस्तृत जांच कराएगी व दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी।

भाजपा ने की न्यायिक जांच की मांग

महाकुंभ के मौके पर इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण हुई श्रद्धालुओं की मौत की भाजपा न्यायिक जांच चाहती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने इसकी जांच की मांग करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही। हादसे के बाद राजनाथ सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री पवन बंसल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात कर तत्काल कदम उठाने की बात कही थी। भाजपा ने पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि हर साल विभिन्न धार्मिक आयोजनों में ऐसी दुखद घटना हो रही है। पार्टी प्रवक्ता श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रेल मंत्री यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं कि मौत भगदड़ के कारण हुई।

आतंकवाद पर 'राष्ट्रीय सहमति' समय की मांग

✍ डॉ. शिव शक्ति बक्सी

21 फरवरी 2013, दिलसुखनगर, हैदराबाद- शाम के लगभग सात बजे होंगे जब दो बम धमाकों ने शहर की शांति को छिन्न-भिन्न कर दिया। अब तक 16 लोगों के मारे जाने और 119 के घायल होने की सूचना आ चुकी है। आतंकी हमले के लिए चुनी गयी जगह, आम तौर पर एक व्यस्त इलाका है जहां बाजार, सिनेमा हॉल और बस पड़ाव स्थित है। धमाकों के समय यह जगह लोगों के आवाजाही से व्यस्त थी जबकि इस हृदय विदारक घटना ने खतरे से अंजान लोगों को अपने चपेट में ले लिया जिसमें कई निर्दोष लोगों की जानें गईं और अनेक लोग लहू-लुहान हो गये। खून से सना दृश्य जिसमें घायल लोग सहायता की पुकार कर रहे थे किसी के भी हृदय को कंपा देने के लिए काफी था। पूरे घटना स्थल पर क्षत-विक्षत लाशे बिखरी पड़ीं थी और घायल अपने को बचाने की जद्दोजहद में चीख-पुकार कर रहे थे। मरने वालों और घायलों में बच्चों से लेकर बूढ़े तक शामिल हैं। इस आतंकी घटना के चपेट में जो भी आये, बच नहीं पाये। घायलों को पास के हस्पतालों में पहुचाया गया जहां वे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जबकि अनेक लोग इस हादसे में अपनी जान गवां चुके हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको इसके फलस्वरूप पूरी जिंदगी अपंगता को ढोना पड़ेगा।

इन बम धमाकों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह पहली बार नहीं है कि निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है। परंतु विडम्बना यह है कि हम तब जागते हैं जब घटना घट चुकी होती है, जब हानि हो चुकी होती है, निर्दोष लोग जान गंवा चुके होते हैं, सैंकड़ों घायल और अपंग बन चुके होते हैं और फिर एकाएक हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आने वाले खतरे से बेखबर चुप बैठ जाते हैं। हर बार जब आतंकी हमला होता है, हम अपनी चिंता और आक्रोश व्यक्त करते हैं परन्तु एक प्रभावी रोकथाम का तंत्र नहीं बना पाते। इस घटना के पूर्व भी गुप्तचर सूचनाएं थीं, पिछले अक्टूबर में ही दिल्ली पुलिस को पता चल चुका था कि इंडियन मुजाहिद्दीन ने दिलसुखनगर क्षेत्र का सर्वे किया है। परन्तु इसके बावजूद इस क्षेत्र में पर्याप्त और प्रभावी पुलिसिया इंतजाम नहीं किये गये।

सन् 2004 में जब कांग्रेस-नीत संप्रग सरकार पहली बार सत्ता में आयी तब जिस जल्दबाजी से 'पोटा' कानून का इसने निरस्त किया, उतना ही 'जल्दबाजी' यह आतंकवाद के रोकथाम में नहीं दिखा पाई। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के फलस्वरूप कांग्रेसनीत संप्रग सरकार जो अब तक आतंकवाद पर ढुलमुल रवैया अपनाई हुई थी, कुछेक कदम उठाने पर बाध्य तो हुई परन्तु अभी तक उसका कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आ पाया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेन्सी, नाटग्रेड तथा आर्गेनाईजेशन ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन न तो आतंकवाद के खतरे को रोक पाई है और ना ही इसके रोकथाम के लिए कोई प्रभावी कदम ही उठा पाई है। यह सब कांग्रेसनीत सरकार द्वारा आधे-अधूरे मन से उठाये गए कदम का परिणाम है। इसके विपरीत यदि हम अमेरिका और इंग्लैंड की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि 9/11 आतंकी हमलों के बाद इन दोनों देशों ने ना केवल कड़े आतंक विरोधी कानून को बनाया बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी नीतियों का भी अनुसरण किया। अमेरिकी गृह विभाग के एक मासिक प्रकाशन में वर्णित अमेरिकी नीति का उल्लेख इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य है:-

- आतंकवाद को ना कोई छूट दिया जाए ना ही इसके साथ कोई समझौता किया जाए।
- आतंकवादियों को उनके अपराध के लिए दण्डित किया जाए।
- जो देश आतंकवाद को प्रश्रय अथवा समर्थन देता हो उसे अलग-थलग किया जाए।
- अमेरिका के सहयोगी देशों में आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को सशक्त बनाया जाए।

उपरोक्त वर्णित चारों बिन्दुओं के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेसनीत संप्रग सरकार इन सिद्धांतों के ठीक विपरीत कार्य करती रही है। सरकार अफजल गुरु के 'क्षमा याचना' के दबाव में रही वह तब जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसे संसद पर हुए आतंकी हमले की सजा दी थी, इस प्रक्रिया के अनावश्यक रूप से देर के कारण इसके विरुद्ध पूरे देश में रोष एवं आक्रोश व्याप्त रहा। अजमल कसाब जो कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दोषी था, के मामले में भी टाल-मटोल का रवैया अपनाया जाता रहा। दूसरे, संप्रग सरकार लगातार आतंकवादी के प्रति ढीला-ढाला रवैया अपनाती रही जिसके कारण इनके हौसले बढ़ते रहे हैं। तीसरी बात यह है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत के आतंकवादियों को मदद एवं समर्थन देती रही है वहीं संप्रग सरकार ने उसके साथ 'हवाना समझौते' पर हस्ताक्षर कर उसकी बात को स्वीकारोक्ति दे दी कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित देश है। जमात-ऊद-दावा के प्रमुख एवं 26/11 मुंबई आतंकी हमले के प्रमुख योजनाकार हाफिज सईद के प्रति आदर सूचक शब्द का प्रयोग करने से भी कांग्रेस नेताओं को गुरेज नहीं है। इतना ही नहीं, गुजरात एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्य जिनकी

पहले भी बिना किसी आधार के 'हिन्दू आतंकवाद' जैसे जुमले गढ़ने का प्रयास किया जा चुका है। जिहादी संगठनों के 'सेक्युलर समर्थक' अपने असली चेहरे को छिपाने के लिए हास्यास्पद एवं मनगढन्त सिद्धांतों को गढ़ 'हिन्दू आतंकवाद' का हौव्वा खड़ा करने का असफल प्रयास करते रहे हैं। उनका आरोप यह भी था कि चूंकि उल्फा के सदस्य हिन्दू हैं इसलिए यह 'हिन्दू आतंकवाद' है। इस तरह के आधारहीन आरोप लगाने वाले भूल जाते थे कि 'उल्फा' किसी हिन्दू मुद्दे को लेकर नहीं बना था। आतंकवादी हमलों, विशेषकर जिहादी संगठनों द्वारा किए गए हिंसक कार्रवाईयों को सही ठहराने के अपने पहले के प्रयासों जिनमें आर्थिक असमानता, शिक्षा की कमी, क्षेत्रीय असंतुलन, अल्पसंख्यकों पर हमले जैसे घिसे-पिटे फार्मूले के असफल हो जाने के बाद, 'सेक्युलर खेमा', 'हिन्दू आतंकवाद' के तर्क गढ़ने के लिए नए-नए बहाने ढूंढ रहा है।

विधानसभाओं ने कड़े आतंक विरोधी कानून पारित किये हैं, राष्ट्रपति के सहमति ना दिए जाने के कारण लटके पड़े हैं। कांग्रेसनीत संप्रग सरकार आतंक के विरुद्ध लड़ाई को तेज कर नेतृत्व देने के स्थान पर रोड़े अटकाने में अधिक दिलचस्पी लेते दिखाई पड़ती है। संप्रग के हाथ 'वोट-बैंक' की मजबूरियों के कारण बंधे पड़े हैं, ना तो यह कोई कार्यवाही कर सकती है ना ही कार्रवाही करने का ढोंग ही कर सकती है।

गृहमंत्री का गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य

संघ-भाजपा पर अपने प्रशिक्षण शिविरों में आतंकवादी प्रशिक्षण के अपने बेतुकों आरोप को हालांकि गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने वापस ले लिया है परन्तु इसके कारण पाकिस्तान में जश्न का माहौल हैं। इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य से आतंकवादी गिरोहों के हौसले बुलंद हुई हैं। पहले भी बिना किसी आधार के 'हिन्दू आतंकवाद' जैसे जुमले गढ़ने का प्रयास किया जा चुका है। जिहादी संगठनों के 'सेक्युलर समर्थक' अपने असली चेहरे को छिपाने के लिए हास्यास्पद एवं मनगढन्त सिद्धांतों को गढ़ 'हिन्दू आतंकवाद' का हौव्वा खड़ा करने का असफल प्रयास करते रहे हैं। उनका आरोप यह भी था कि चूंकि उल्फा के सदस्य हिन्दू हैं इसलिए यह 'हिन्दू आतंकवाद' है। इस तरह के आधारहीन आरोप लगाने वाले भूल जाते थे कि 'उल्फा' किसी हिन्दू मुद्दे को लेकर नहीं बना था।

आतंकवादी हमलों, विशेषकर जिहादी संगठनों द्वारा किए गए हिंसक कार्रवाईयों को सही ठहराने के अपने पहले के प्रयासों जिनमें आर्थिक असमानता, शिक्षा की कमी, क्षेत्रीय असंतुलन, अल्पसंख्यकों पर हमले जैसे घिसे-पिटे फार्मूले के असफल हो जाने के बाद, 'सेक्युलर खेमा', 'हिन्दू आतंकवाद' के तर्क गढ़ने के लिए नए-नए बहाने ढूंढ रहा है। जबकि 'सिमी' पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसका नया अवतार 'इंडियन मुजाहिद्दीन' हैदराबाद सहित विभिन्न शहरों पर आतंकवादी हमले कर रहा है जिसमें जान-माल का भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में 'हिन्दू आतंकवाद' का जुमला गढ़ देश को भरमाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इस तरह के रवैये से देश में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई कमजोर हुई है।

निष्कर्ष

आतंकवाद पूरे मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। हाल के वर्षों में इसका अंतराष्ट्रीय नेटवर्क भी सामने आया है और अब विश्व के किसी भी हिस्से को यह अपने निशाने पर ले सकता है। एक दूसरी गंभीर बात विभिन्न आतंकवादी संगठनों के बीच के संबंधों को लेकर है जिसके अंतर्गत पाया गया है कि विभिन्न एवं यहां तक कि विपरीत विचारधाराओं के रहते हुए भी इनके बीच एक खतरनाक गठ-जोड़ है। आतंकवाद एक फायदे का उद्योग बनकर उभर रहा है तथा समानांतर आर्थिक-राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति बनने के मंसूबे पाले हुए हैं। नक्सल-माओवादी गुटों द्वारा सिमी को समर्थन दिया जाना ऐसे ही खतरनाक गठजोड़ का एक उदाहरण है। 9/11 आतंकी हमले जिससे कि विश्व ने आतंक के खौफनाक चेहरे को देखा से बहुत पहले भारत इसके खतरनाक हमलों के निशाने पर रहा है। एक आंकड़े के अनुसार 1970 के दशक के अंतिम वर्षों से ही भारत विदेश समर्थित आतंक का दंश झेल रहा है जिसके अंतर्गत पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर-पूर्व एवं देश के अन्य भागों में 80,000 से अधिक सामान्य नागरिक एवं सुरक्षा बल के लोगों ने अपने प्राण गंवाये हैं।

लगातार हो रहे आतंकी हमले के जवाब में भारत सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ढीला-ढाला एवं कमजोर रहा है। कांग्रेसनीत संप्रग सरकार हर आतंकी हमले के बाद असहाय होने का अहसास दिलाने से अधिक कुछ नहीं कर पाई है।

हमारी राजव्यवस्था के बुद्धिजीवी वर्ग, मीडिया, नीतिनिर्माता, राजनीतिक तंत्र, सामाजिक कार्यकर्ता, न्यायपालिका तथा सभी अन्य महत्वपूर्ण घटकों को मिलाकर आतंकवाद पर एक आम सहमति बनानी होगी और इसे कार्यान्वित करने के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता दर्शानी होगी। समय आ गया है कि हम आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए ठोस और कारगर उपाय प्रारम्भ करें। राजनीति के विभिन्न स्तरों पर एक सहमति बनाने का प्रयास कर इन खतरों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है जो हमारे भविष्य के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरु किये जा सकते हैं:-

- सीमापार आतंकवाद, अलगाववादी आतंकी गतिविधियों, नक्सल हिंसा, विध्वंसात्मक तथा विनाशकारी तत्वों एवं अन्य ऐसे ही तत्वों से उत्पन्न दीर्घ एवं अल्पकालीन खतरों से निपटने के लिए आंतरिक सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए।
- सुरक्षा खतरों की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को देखते हुए एक दीर्घकालीन नीति बनाने पर भी आम सहमति होनी चाहिए। इस प्रसंग में यह नीतियां ज्यों की त्यों बनी रहनी चाहिए, भले ही सरकारें बदल जाएं परन्तु विभिन्न स्तरों पर इनका कार्यान्वयन होना चाहिए।
- सुरक्षा खतरों के कारण आतंकवादियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय अखण्डता के लिए जो भी उपाय शुरु किये जाते हैं या इस सम्बन्ध में किये गये किसी भी प्रकार के उपायों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
- आतंकवादियों, अलगाववादियों, विध्वंसात्मक और विनाशकारी तत्वों से वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
- इस बात पर आम सहमति होनी चाहिए कि हम राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर बजट का एक निश्चित अनुपात सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए रखें ताकि सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध रहे।
- राष्ट्र के गुप्तचर विभाग को पूरी तरह से दुरुस्त करना होगा और आपसी तालमेल का मुद्दा इस ढंग से निर्धारित करना होगा जिससे किसी प्रकार की खामी न रहे।
- आतंक-विरोधी कानून का होना अनिवार्य है, ऐसा न हो नीतियां बदलती जाएं जैसे किसी समय 'टाडा' था तो फिर उसे समाप्त कर दिया गया या 'पोटा' बनाया गया तो सरकार के बदलने से उसे निरस्त कर दिया गया- इस तरह की स्थिति को दरकिनार किया जाना चाहिए।
- एक विशेषज्ञ दल नियुक्त होना चाहिए जो दीर्घकालीन सुरक्षा नीतियों के आयोजन और कार्यान्वयन पर स्थायी रूप से काम करे और ये नीतियां सरकार के बदलने के बावजूद भी काम करती रहें।

आतंकवाद पूरे मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। हाल के वर्षों में इसका अंतराष्ट्रीय नेटवर्क भी सामने आया है और अब विश्व के किसी भी हिस्से को यह अपने निशाने पर ले सकता है। एक दूसरी गंभीर बात विभिन्न आतंकवादी संगठनों के बीच के संबंधों को लेकर है जिसके अंतर्गत पाया गया है कि विभिन्न एवं यहां तक कि विपरीत विचारधाराओं के रहते हुए भी इनके बीच एक खतरनाक गठ-जोड़ है।

शेष पृष्ठ 20 पर

मार्कण्डेय काटजू को भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष पद से क्यों इस्तीफा दे देना चाहिए

✍ अरुण जेटली

पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और वर्तमान में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू ने लोकप्रिय तरीके से निर्वाचित दो गैर कांग्रेस राज्य सरकारों और उसके नेताओं को चुनकर निशाना बनाया। उन्होंने प्रेस परिषद की ओर से एक रिपोर्ट का प्रारुप जारी कर आरोप लगाया कि बिहार में मीडिया स्वतंत्र नहीं है। उन्होंने 'द हिन्दू' के एक लेख में गुजरात सरकार और उसके मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा।

आरंभ में अपनी विद्वता के लिए मशहूर न्यायमूर्ति काटजू कभी भी एक पारंपरिक न्यायाधीश नहीं रहे। न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान और उसके बाद उनके कथन हमेशा विचित्र रहे हैं। सम्मानजनक टिप्पणी से उनका बैर है। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल, बिहार या गुजरात की गैर कांग्रेस सरकारों पर उनका हमला उन लोगों को धन्यवाद देने के लिए है जिन्होंने रिटायर होने के बाद उन्हें यह पद प्रदान किया है।

मेरा यह दृढ़ मत है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को रिटायर होने के बाद सरकार में नौकरी के योग्य नहीं माना जाना चाहिए। कुछ मामलों में किसी न्यायाधीश का रिटायर होने से पहले का आचरण रिटायर होने के बाद मिलने वाले पद की इच्छा से प्रेरित होता है। हम अभी भी ऐसी व्यवस्था चला रहे हैं जहां विभिन्न न्यायाधिकरणों और अन्य अर्द्धन्यायिक पदों पर रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है।

भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष हमेशा से उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा है। वह प्रेस की आजादी, उसकी आजादी के संभावित अतिक्रमण से संबंधित मामलों को देखता है और मीडिया रिपोर्टिंग और टिप्पणी में पेशेवर अंदाज की कमी से संबंधित शिकायतों को सुनता है। प्रेस परिषद का अध्यक्ष वैधानिक कार्य करता है। उसका काम न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और राजनैतिक रुप से तटस्थ होना चाहिए। साथ ही एक न्यायाधीश, चाहे वह वर्तमान या सेवानिवृत्त है, उससे अपेक्षा की जाती है कि उसका आचरण गंभीर, सभ्य और सम्मानजनक हो। वह ऊंचे स्वर वाला, असभ्य, विचित्र या अहंकारपूर्ण व्यवहार करने वाला नहीं होना चाहिए। जब न्यायाधीश न्यायिक कार्य करते हैं कोई भी उनकी मंशा नहीं जान सकता। यहां तक कि फैसलों की आलोचना संयमित भाषा में होनी चाहिए। आलोचना सैद्धांतिक हो सकती है व्यक्तिगत नहीं। यह न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक कामकाज का मौलिक सिद्वांत है कि एक न्यायाधीश को राजनैतिक विवादों में खुद को शामिल करने से परहेज करना चाहिए। अगर उसकी इच्छा राजनैतिक गतिविधियों या राजनैतिक बहस में शामिल होने की है, तो उसे अपने न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक पद को छोड़ देना चाहिए। किसी भी तरह देखा जाए तो उनके विचारों के मामले पर भी उसी तरह बाल की खाल निकाली चाहिए जैसे राजनीतिज्ञों के मामले में किया जाता है।

न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू उस परीक्षा में विफल रहे हैं जिसमें किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश का आकलन किया जाता है। उनके विषय और लक्ष्यों का चयन उनकी राजनैतिक पसंद से प्रेरित है। वह उन लोगों के प्रति बेहद नरमी बरतते हैं जिन्होंने रिटायर होने के बाद उन्हें काम दिया है। मुझे उनकी ऐसी एक भी टिप्पणी पढ़ने को नहीं मिली है जिसमें नेतृत्व के मामले में वंशवाद की जगह प्रतिभाओं को

भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष हमेशा से उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा है। वह प्रेस की आजादी, उसकी आजादी के संभावित अतिक्रमण से संबंधित मामलों को देखता है और मीडिया रिपोर्टिंग और टिप्पणी में पेशेवर अंदाज की कमी से संबंधित शिकायतों को सुनता है। प्रेस परिषद का अध्यक्ष वैधानिक कार्य करता है। उसका काम न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और राजनैतिक रुप से तटस्थ होना चाहिए। साथ ही एक न्यायाधीश, चाहे वह वर्तमान या सेवानिवृत्त है, उससे अपेक्षा की जाती है कि उसका आचरण गंभीर, सभ्य और सम्मानजनक हो। वह ऊंचे स्वर वाला, असभ्य, विचित्र या अहंकारपूर्ण व्यवहार करने वाला नहीं होना चाहिए।

प्राथमिकता देने की चर्चा की गई हो। जाहिर है इस तरह की टिप्पणियों से उन लोगों को शर्मिंदा होना पड़ेगा जिनकी इच्छा भारत को वंश परम्परा के लोकतंत्र को वैध बनाने की है। न्यायमूर्ति काटजू के धर्मयोद्धा ने उस वक्त खुद पर नियंत्रण रखा जब 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन से लेकर कोयला ब्लॉक आबंटन तक यूपीए के भ्रष्टाचार की आलोचना की जा रही थी। जब बिहार में व्यवस्था में बदलाव की देश और विदेश में एक बड़े वर्ग द्वारा सराहना और राजनीति के केन्द्र में विकास के उद्भव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, न्यायमूर्ति काटजू ने प्रेस की आजादी की कमी के लिए नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर निशाना साध दिया।

'द हिन्दू' में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना से भरा उनका लेख व्यक्तिगत निंदा से भरा हुआ लगता है। उनका राजनीतिक झुकाव इस तथ्य से स्पष्ट है कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के जलने पर उन्होंने लिखा- ''यह अभी भी रहस्य है कि गोधरा में क्या हुआ?'' क्या न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू उन लोगों की वकालत करना चाहते हैं जिन्हें ट्रेन को आग लगाने का दोषी ठहराया गया है जिसके कारण अनेक लोगों की जानें गईं और कई लोग घायल हुए। क्या उच्चतम न्यायालय का एक पूर्व न्यायाधीश जो इस समय एक वैधानिक पद पर है इस तथ्य की अनदेखी कर सकता है कि मामले में निचली अदालत ने अनेक आरोपियों को दोषी ठहराया है और उनकी अपील लंबित है?

बाद में उन्होंने इस तथ्य पर टिप्पणी की कि किसी भी न्यायिक प्राधिकरण ने प्रथम दृष्टया नरेन्द्र मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। उन्होंने न्यायिक फैसले पर बाजार में गर्म अफवाहों को प्राथमिकता दी और कहा, ''मैं अपनी न्यायिक व्यवस्था पर टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन निश्चित तौर पर मैं इस कहानी पर यकीन नहीं करता कि 2002 में नरेन्द्र मोदी का हाथ नहीं है।''

उन्होंने मोदी और गुजरात के खिलाफ अपने आक्षेप जारी रखे और गुजरात में आर्थिक विकास को कम करके आंका। उनकी टिप्पणी थी- ''बड़े औद्योगिक घरानों को रियायत, उन्हें सस्ती जमीन और सस्ती बिजली देने को शायद ही विकास कहा जा सकता है अगर उससे लोगों का जीवन स्तर ऊपर न उठे।'' उन्होंने अपनी बात को सही साबित करने के लिए चुनकर कुछ आंकड़े रखे। प्रोफेसर जगदीश भगवती और डा. अरविंद पनगड़िया ने अपने हाल के प्रकाशनों में टिप्पणी की है कि गुजरात को आजादी के समय निचले स्तर के सामाजिक संकेतक मिले थे और इन संकेतकों में बदलाव है जब गुजरात में प्रभावशाली सुधार देखने को मिला है। साक्षरता दर जो 1951 में 22 प्रतिशत थी वह 2001 में 69 प्रतिशत हो गई और 2011 में यह 79 प्रतिशत पर पहुंच गई। शिशु मृत्यु दर 1971 में प्रति एक हजार शिशुओं पर 144 थी जो 2001 में 60 और 2011 में 41 पर आ गई। गुजरात के मामले में वह पूर्वाग्रहों से प्रेरित हैं।

न्यायमूर्ति काटजू ने अपने लेख का समापन राजनीतिक अपील के साथ किया है। उनकी टिप्पणी है, ''मैं भारत की जनता से अपील करता हूं कि अगर उसे देश के भविष्य की चिंता है तो वह इन सभी बातों पर गौर करे, अन्यथा वह वही गलती कर सकती है जो जर्मनी के लोगों ने 1933 में की थी।'' मैं न्यायमूर्ति काटजू के राजनैतिक विचार रखने के अधिकार को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसका कार्य अर्द्ध-न्यायिक है खुलकर राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकता है। उनकी अपील राजनीतिक है। वह कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कांग्रेस लगते हैं। अगर उच्चतम न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश राजनीति में इतना खुलकर शामिल हो और एक राजनैतिक अपील करे तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगर एक सरकारी अधिकारी यही काम करे तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। क्या एक पूर्व न्यायाधीश जो भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रुप में एक अर्द्ध-न्यायिक पद पर है, उसे राजनीति में सक्रिय रुप से भाग लेने से पहले इस्तीफा नहीं देना चाहिए या उसे पद से हटा नहीं देना चाहिए। रिटायर्ड न्यायाधीशों को याद रखना चाहिए कि रिटायर होने के बाद लुटियन जोन में रहने के लिए उन्हें राजनैतिक तौर पर तटस्थ रहना होगा न कि राजनीति में दखल देना चाहिए।■

(लेखक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं।)

न्यायमूर्ति काटजू ने अपने लेख का समापन राजनीतिक अपील के साथ किया है। उनकी टिप्पणी है, ''मैं भारत की जनता से अपील करता हूं कि अगर उसे देश के भविष्य की चिंता है तो वह इन सभी बातों पर गौर करे, अन्यथा वह वही गलती कर सकती है जो जर्मनी के लोगों ने 1933 में की थी।'' मैं न्यायमूर्ति काटजू के राजनैतिक विचार रखने के अधिकार को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसका कार्य अर्द्ध-न्यायिक है खुलकर राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकता है। उनकी अपील राजनीतिक है। वह कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कांग्रेस लगते हैं।

अगस्टा वैस्टलैंड सौदा संप्रग का एक और नया घोटाला

विकाश आनन्द

जिस तरह से गत एक दशक में एक के बाद एक घोटालों के मामले आये हैं उससे लगता है कि कांग्रेसनीत संप्रग घोटालों की पर्याय हो गई है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद फरोख्त के बड़े पैमाने पर दलाली का मामला सामने आया है। वोट के बदले नोट, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, 2जी घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला अब वीवीआईपी हैलीकॉप्टर सौदा घोटाला। जिस तरह कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के लगभग एक दशक के कार्यकाल में घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, उससे यह महमूद गजनी की याद दिलाती है। महमूद गजनी एक ऐसा बाहरी आक्रमणकारी था जिस का भारत को लूटना ही केवल मकसद था। उसने भारत को सत्रह बार लूटा।

अगस्टा वैस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर सौदा घोटाला का लक्षण काफी हद तक बोफोर्स से मिलता-जुलता है। बोफोर्स की तरह इसका भी तार इटली से जुड़ा हुआ है।

मुख्य विपक्षी दल भाजपा इस 3500 करोड़ से अधिक की 124डब्ल्यू101 हैलीकॉप्टर के खरीद-फरोख्त में हुई दलाली के मामले की जांच कोर्ट द्वारा नियंत्रित सीबीआई से कराने की मांग की है। संप्रग सरकार के शासनकाल में किसी भी बड़े मामले में सीबीआई ने कोई परिणाम नहीं दिया है। इसलिए भाजपा ने कोर्ट द्वारा नियंत्रित सीबीआई जांच की मांग इस हैलीकॉप्टर सौदे घोटाले में की है।

मुख्य विपक्षी दल भाजपा इस 3500 करोड़ से अधिक की 124डब्ल्यू101 हैलीकॉप्टर के खरीद-फरोख्त में हुई दलाली के मामले की जांच कोर्ट द्वारा नियंत्रित सीबीआई से कराने की मांग की है। संप्रग सरकार के शासनकाल में किसी भी बड़े मामले में सीबीआई ने कोई परिणाम नहीं दिया है। इसलिए भाजपा ने कोर्ट द्वारा नियंत्रित सीबीआई जांच की मांग इस हैलीकॉप्टर सौदे घोटाले में की है।

पिछले साल दिसम्बर महीने में वीवीआईपी हैलीकॉप्टर सौदे में दलाली का मामला इटली और भारतीय मीडिया में आया उसी समय भाजपा ने संसद में इस मामले को उठाया। राज्यसभा सदस्य श्री प्रकाश जावडेकर ने 14 दिसम्बर 2012 को रक्षामंत्री ए.के. एंटोनी को पत्र लिख कर इस मामले में स्वप्रेरणा से एक निर्धारित समय-सीमा के अंदर जांच कराने की मांग की। भारत सरकार ने इस मांग को टाल दिया। लेकिन इटली की सरकार ने इसे गम्भीरता से लेते हुए जांच कराना शुरू कर दिया।

श्री जावडेकर ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि समाचार रिपोर्टों से पता चला कि भारत सरकार की कोई आंतरिक जांच हो रही है और वह सौदे को क्लीनचिट देने वाली है। भाजपा ने मांग की है कि जो आंतरिक जांच हुई है उसकी पूरी रिपोर्ट दी जाए और बताया जाए कि कैसे सौदे में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।

उन्होंने बताया कि सरकार बिना किसी जांच का हवाला देते हुए किसी भारतीय एजेंसी से औपचारिक जांच में

असमर्थता जतायी। सरकार का कहना है कि मेरे पास तो इसके बारे में कोई विशेष सूचना नहीं है।

भारत सरकार इटली से बिना किसी आधिकारिक सूचना के जांच करा सकती थी। क्योंकि हासचके Haschke और गेरोसेस (Geroses) के बीच इस संबंध हुई बातचीत के टेप चार महीने से सार्वजनिक हैं। सरकार के इसी रवैये के कारण फिनमेकनिका का भारत का चीफ जो कि इस दलाली से जुड़ा हुआ है भारत से भाग गया। रक्षामंत्री तकनीकी दिक्कतों का बहाना बनाकर इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं।

करीब 3600 करोड़ रुपये में 12 हेलिकॉप्टरों के सौदे में बड़ा घोटाला यूपीए के कार्यकाल में हुआ। यह डील हासिल करने के लिए भारत में 362 करोड़ रुपये की रिश्वत देने के आरोप में इटली की सरकारी कंपनी फिनमेकनिका के प्रमुख जूसेपी ओरसी को इटैलियन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिनमेकनिका की सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के प्रमुख ब्रूनो स्पैगनेलेनी को भी इटली की कोर्ट ने नजरबंद करने के आदेश दिए हैं। बाकी 9 हेलिकॉप्टरों की डील स्थगित कर दी।

वैसे तो इस डील में कथित रिश्वतखोरी की खबरें पिछले साल इटली की मीडिया में आई थीं। एक भारतीय और एक ब्रिगेडियर का नाम भी सामने आया था। भारत सरकार इटली सरकार से पूरी जानकारी न मिलने की बात कहकर इसे नजरअंदाज करती रही।

फिनमेकनिका अगस्टा वैस्टलैण्ड की मदर कम्पनी है। इस इटालियन कम्पनी में आपसी उत्तराधिकार की लड़ाई ने अगस्टा वैस्टलैण्ड का भारत के साथ हैलीकॉप्टर सौदे में हुए भ्रष्टाचार से पर्दा उठाया। कम्पनी में इटली सरकार सबसे बड़ी शेयरहोल्डर है। इसलिए इटली सरकार ने तुरन्त जांच शुरू की और मुख्य बिचौलिया गीडो हास्चेकल्सो (Gwido Haschkealso) ने इसमें भ्रष्टाचार के मामले को स्वीकार किया।

भारत के समाचार पत्रों में प्रकाशित इटली सरकार की जांच रिपोर्ट के अनुसार कैसे और कब यह घोटाला हुआ का सारांश उद्धृत है-

पृ.सं. 1-2 : इटली की जांच रिपोर्ट के पहले दो पन्ने हैलीकॉप्टर घोटाले के मुख्य अभियुक्तों के बारे में जानकारी देता है। इसमें फिनमेकनिका के सीईओ कम्पनी के दूसरे अधिकारी और बिचौलिया गीडो हास्चके और क्रिश्चियन माइकल तथा साथ ही साथ भारत में किसको-किसको पैसा दिया गया है का जिक्र है। विशेषकर दूसरे पृष्ठ पर पूर्व वायुसेना प्रमुख एस.पी. त्यागी जिन्होंने अगस्टा वैस्टलैण्ड का काँट्रेक्ट दिलवाने में मदद किया को उनके चचरे भाईयों के द्वारा पैसा दिलवाने की चर्चा की गई है।

पृष्ठ सं. 3-6 : इन पृष्ठों में इटालियन जांचकर्ताओं ने बताया है कि कैसे बोगस इंजीनियरिंग काँट्रेक्ट तुनिसिया और इंडिया की आई.डी.एस कम्पनी को साथ करके इसके द्वारा पैसे बिचौलियों में बांटा गया है। इस चैनल द्वारा कुल दलाली 21 मिलियन यूरो भुगतान किया गया है। मनी चार्ट बताता है कि 2007-11 के बीच मासिक किस्तों में यह दलाली अदा किया गया है। यह भुगतान प्रत्येक महीने औसतन लगभग 550,000 यूरो है।

3500 करोड़ की डील

इन वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों के लिए भारत ने फिनमेकनिका कंपनी के साथ फरवरी 2010 में डील साइन की थी। इसके तहत करीब 3500 करोड़ रुपये में 12 एडब्ल्यू-101 हेलिकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं। तीन की डिलीवरी हो चुकी है, जिन्हें वायुसेना के संचार स्क्वॉड्रन को सौंप दिया गया है, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य बड़ी हस्तियों को हेलिकॉप्टर के जरिए लाने-ले जाने की जिम्मेदारी संभालती है। बाकी हेलिकॉप्टर अगले साल के मध्य तक मिलने थे।

पृष्ठ सं. 7-11 : जांच 2011 में शुरू हुई जब उत्तराधिकार की लड़ाई गुआरगुआगलिनी और ओरसी के बीच शुरू हुई। गुआरगुआगलिनी फिनमेकनिका का प्रमुख था। बाद में इसकी जगह ओरसी ने ली। कम्पनी का एक पूर्व बड़ा अधिकारी लोरेन्जो बोरगोगनी ने जांचकर्ताओं को बताया कि दलाली इस कॉन्ट्रेक्ट के लिए अगस्टा वैस्टलैण्ड द्वारा लगभग 51 मिलियन यूरो भुगतान किया गया है। पैसा बिचौलिया और कंसल्टेंट के एक नेटवर्क द्वारा दिया गया है।

पृष्ठ सं. 12-16 : इन पृष्ठों में मुख्य बिचौलिया गीडो हासचके ने किस तरह अपराध स्वीकार किया है, उसका विवरण है। इसमें यह बताया कि त्यागी जब वायुसेना प्रमुख थे तो कई बार वह उनसे मिला। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने दलाली लगभग बीस मिलियन यूरो लिया जिसमें 12 मिलियन त्यागी भाईयों को दिया।

इटली के जांचकर्ताओं को एक

शेष पृष्ठ 26 पर

कांग्रेस ने किया फतह भ्रष्टाचार का ऐवरेस्ट

✍ अम्बा चरण वशिष्ठ

कांग्रेस के भ्रष्टाचार की घड़ी लगातार टक-टक करती जा रही है। जब तक कि 2014 के लोक सभा चुनाव की घंटी बजेगी तब तो शायद अनेकों और भ्रष्टाचार के घोटाले सामने आ चुके होंगे। कांग्रेस ने तो अपने शासनकाल में एक-एक कर इतने भ्रष्टाचार के मामले खड़े कर दिये कि अब तो वह ऐवरेस्ट की चोटी से भी इतने ऊंचे हो गये है कि शायद ही कोई और इतनी ऊंचाई तक पहुंच पायेगा।

नवीनतम वीवीआईपी हैलिकाप्टर घोटाले व बोफोर्स तोप घोटाले में कई समानतायें हैं। दोनों का सम्बन्ध रक्षा मन्त्रालय से है। दोनों में ही इटली का सम्बन्ध है। दोनों ही कांग्रेस सरकारों के समय घटित हुये। दोनों ही समय रक्षा मन्त्री कांग्रेस के थे। दोनों ही मामलों में यह दावा किया गया था कि इन सौदों में कोई बिचौलिया नहीं है और इन में कोई घूस न ली गई न दी गई। पर बाद में यह दावा झूठ ही निकला।

दोनों ही बार रक्षा मन्त्रालय इन घोटालों में घूस की बू सूंघ पाने में असमर्थ निकला। प्रश्न तो यह उठता है कि रक्षा मन्त्रालय का अन्वेषण व खुफिया विभाग क्या करता है? यदि रक्षा मन्त्रालय का खुफिया विभाग यह ही नहीं जान सकता कि उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है तो वह दुश्मन की गतिविधियों पर क्या निगरानी रख पायेगा?

दोनों घोटालों की भनक न सरकार को लगी न रक्षा मन्त्रालय को। दोनों ही बार सरकार को उसकी गहरी नींद से जगाया। विदेशी समाचार पत्रों ने –

कांग्रेस के भ्रष्टाचार की घड़ी लगातार टक-टक करती जा रही है। जब तक कि 2014 के लोक सभा चुनाव की घंटी बजेगी तब तो शायद अनेकों और भ्रष्टाचार के घोटाले सामने आ चुके होंगे। कांग्रेस ने तो अपने शासनकाल में एक-एक कर इतने भ्रष्टाचार के मामले खड़े कर दिये कि अब तो वह ऐवरेस्ट की चोटी से भी इतने ऊंचे हो गये है कि शायद ही कोई और इतनी ऊंचाई तक पहुंच पायेगा।

बोफोर्स घोटाले का पर्दाफाश किया- स्वीडिश रेडियो ने और वीवीआईपी हैलिकाप्टर घोटाले को स्वयं इटली सरकार ने।

इस घोटाले की खबरें तो पिछले एक वर्ष से भारत और विदेश में अनेक अखबारों की सुर्खियों में थीं। पर सरकार के कान पर जूं न रेंगी और उसने जानबूझ कर जांच करवाने से आंख मूंद रखी, यह बहाना लगा कर कि सरकार अखबारों में छपी खबरों के आधार पर कुछ नहीं कर सकती। पर प्रश्न तो यह है कि सरकार ने इन रिपोर्टों के बाद भी तथ्य खंगालने की ज़हमत क्यों नहीं उठाई?

यहां तक कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व सांसद श्री प्रकाश जावडेकर ने यह मामला राज्य सभा में उठाया तो सरकार कार्यवाही के लिये तब भी तैयार न हुई। बस इधर-उधर की बातें कर मामले को टालती रही। अब कारण स्पष्ट होने लगे हैं। सरकार पहले की तरह अपराधियों को अपना बचाव पैदा करने का समय दे रही थी। यह तो इस समाचार से भी स्पष्ट हो रहा है कि हैलिकाप्टर कम्पनी ने 317 करोड़ रुपये की राशि 3600 करोड़ रुपये के इस सौदे को पाने के लिये घूस देने के लिये अलग रख रखी थी।

इटली सरकार द्वारा दायर मुकद्दमें में कहा गया है कि बिचौलिये इस 12 हैलिकाप्टरों की खरीद के सौदे को करवाने के लिये साढ़े सात प्रतिशत कमीशन लेने पर राज़ी हो गये थे। अन्ततः घूस की यह राशि 362 करोड़ रुपये पहुंच गई थी।

भाजपा ने सरकार पर यह बताने के लिये दबाव बढ़ा दिया है कि वह उन व्यक्तियों के नाम बताये जिन्हें इस सौदे से किन भारतीयों को घूस मिली और इटली की अदालत में पेश कागज़ात में 'दि फैमिली' (परिवार) कौन है?

भाजपा ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझ कर मामले को इधर-उधर उलझाने का प्रयास कर असल अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है। उसने कहा है कि मामला अगर-मगर का नहीं है बल्कि दोषियों को सज़ा दिलाने का जिसमें सरकार कोताही बरत रही है।

भाजपा ने कहा है कि सारा उत्तरदायित्व मनमोहन सरकार का बनता है जिसने अन्ततः इस सौदे को सम्पन्न किया।

सरकार के रवैयये से तो 'चोरी और सीनाज़ोरी' वाली कहावत ही चरितार्थ

शेष पृष्ठ 29 पर

देश की तरफ नजर उठाने वालों को कड़ा संदेश

✍ चंदन मित्रा

आखिरकार एक दशक से भी लंबे इंतजार के बाद अफजल गुरु को फांसी पर लटका दिया गया। भारतीय जनता पार्टी अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने की मांग लंबे समय से करती आ रही थी। इस लिहाज से पार्टी ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। इस कदम का न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि हर देशभक्त इंसान स्वागत कर रहा है। अफजल गुरु को फांसी की सजा हुए भी एक दशक बीत चुका था। इस दौरान कानूनी प्रक्रिया को विधिवत रूप से अपनाया गया था। लिहाजा, उसे जल्द से जल्द फंसी दे देनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की ओर से इस मामले में खूब देरी की गई।

अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने का श्रेय कांग्रेस और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ले रही है। लेकिन उसे दूसरी ओर इस देश की जनता को यह भी बताना चाहिए कि इस काम में आखिरकार किन वजहों से इतनी देरी हुई। यह बात सरकार को आम लोगों को बतानी चाहिए। वैसे अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने का असली श्रेय देश के मौजूदा राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी को जाता है। उनके इस फैसले से देश की ओर आंख उठाकर देखने वोलों को एक कड़ा संदेश मिल चुका है। उनके पास जब यह फाइल पहुंची, उन्होंने इस दिशा में तेजी से कदम उठाए। इसका नतीजा है कि एक दशक बाद ही सही लेकिन अफजल गुरु को फांसी हो पाई। लेकिन संसद पर हुए आतंकी हमले में जिन लोगों की मौत हुई थी, उनके परिवारों के लिए यह फांसी भी इंसाफ देने वाला नहीं माना जा सकता। क्योंकि न्याय मिलने में देरी हुई है।

लेकिन इस फैसले का फायदा कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उसकी कोशिश इस कदम के जरिए हिंदू मतदाताओं को लुभाने की होगी। लेकिन आम जनता को यह साफ नजर आ रहा है कि कांगेस दोनों तरफ से लाभ हासिल करने की कोशिश कर रही है। यह उसकी फितरत में शुरू से शामिल रहा है। एक तरफ तो केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भगवा आतंकवाद का नाम लेकर मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर रिझा रहे हैं, तो दूसरी ओर अफजल गुरु की फांसी के बहाने हिंदू मतदाताओं पर डोरे डाल रहे हैं। इस दोतरफी राजनीति को आम जनता खूब समझ रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका सबक भी मिल जाएगा। उसे न तो हिंदू मतदाताओं का भरोसा हासिल होने जा रहा है और न ही मुस्लिम मतदाता उसका साथ देंगे।

> ***अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने का श्रेय कांग्रेस और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ले रही है। लेकिन उसे दूसरी ओर इस देश की जनता को यह भी बताना चाहिए कि इस काम में आखिरकार किन वजहों से इतनी देरी हुई। यह बात सरकार को आम लोगों को बतानी चाहिए। वैसे अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने का असली श्रेय देश के मौजूदा राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी को जाता है।***

अफजल गुरु के फांसी को मंजूरी देने का फैसला राष्ट्रपति महोदय का है, मैं मानता हूं कि इसमें उन्होंने अपनी ओर से एक सही फैसला लिया, जिसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन इस मामले में कांग्रेस और यूपीए सरकार ने जिस तरह की तेजी दिखाई, उससे मुझे यह कांग्रेसी रणनीति का हिस्सा भी लग रहा है। संसद के बजट सत्र से ठीक पहले इतना बड़ा फैसला बिना राजनीतिक मकसद के हो भी नहीं सकता। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने संसद सत्र के दौरान सुशील कुमार शिंदे का बॉयकॉट करने का एलान किया हुआ था। हिंदू आतंकवाद के नाम पर उन्होंने जिस तरह का गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया था, उससे उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ता। इसे भांपते हुए कांग्रेस ने अफजल गुरु के फांसी के बहाने अपने गृहमंत्री को उस आंच से बचाने की कोशिश की है।

इसके अलावा कांग्रेस ने जिस तरह

शेष पृष्ठ 29 पर

यूपीए ने महिला सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया : स्मृति ईरानी

भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी का मानना है कि जब तक महिलाओं को इस बात का विश्वास नहीं होगा कि कानून अमल में नहीं आएगा, शासन अच्छा नहीं होगा तब तक कोई ठोस सुधार आना मुश्किल है। उन्होंने यूपीए सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि यह सरकार महिलाओं के मन में विश्वास जगा पाने में पूर्णत: विफल साबित हो रही है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि भाजपा पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने महिला सुरक्षा विषय को लेकर संसद के विशेष सत्र की मांग की और इसके साथ ही हमने देशभर में चर्चा और आंदोलन के माध्यम से जन-जागरण करने का प्रयास किया।

पिछले दिनों महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों को लेकर श्रीमती स्मृति ईरानी से उनके नई दिल्ली स्थित निवास पर कमल संदेश के सहायक संपादक **संजीव कुमार सिन्हा** *ने लम्बी बातचीत की, जिसके मुख्यांश यहां प्रस्तुत हैं :*

देश में महिलाओं की वर्तमान स्थिति से आप कितना संतुष्ट हैं?

देश की 120 करोड़ की आबादी में आधी जनसंख्या महिला की है। लेकिन जब बजट बनाया जाता है, तब क्या उस महिला के बारे में आधी चिंता भी की जाती है, यह बहुत बड़ा सवाल है। जो नौंवी पंचवर्षीय योजना थी उसमें वीमेन कांपोनेंट प्लान था, जिसके हिसाब से सरकार को दिशानिर्देश था कि अगर आप बजट बनाते हैं तो 33 प्रतिशत महिला संबंधी कार्यों में लगाएंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले दो बजट सत्रों से जो मैं देख रही हूं संसद में, 5 प्रतिशत भी महिला संबंधित कार्यों में नहीं लगाया जाता। यह सरकार बढ़-चढ़कर महिला के अधिकारों की चर्चा बहुत करती है लेकिन इसी सरकार के नुमाइंदे, जो साधारण नागरिक महिला सुरक्षा में अग्रिम भूमिका निभाते हैं दिल्ली की सड़कों पर, तब हम उसका स्वागत लाठीचार्ज से करते हैं। आज देश में चर्चा जब हो रही है बलात्कार को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर तो देश का दुर्भाग्य यह है कि आज भी महिला अगर रात को अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है तो सुरक्षा अपने लिए लेने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगी। जो सरकार और पुलिस महकमा अब तक इस स्वतंत्र भारत में एक भारतीय महिला में इतना भी विश्वास नहीं जगा पाए, इसका मतलब सरकार और व्यवस्था पूर्णत: विफल हो चुकी है।

इन दिनों महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं लगातार प्रकाश में आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है?

मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में कहीं न कहीं अखबारों की सुर्खियों में बलात्कार व छेड़छाड़ की घटनाएं बहुत आती है। सजा के बारे में कभी इतनी चर्चा नहीं होती, न ही समाचार आते हैं। एक महिला अन्याय के खिलाफ बोलने में प्रोत्साहित कब होगी, जब उसे लगता है कि सिस्टम कहीं न कहीं उसका सहयोग करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन सबसे पहले महिला को इस प्रश्न से जूझना पड़ता है कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ या तुम्हारे साथ छेड़खानी हुई। जब तक हम यह सोच बदल नहीं देते देश में या समाज में, तब तक यह हिचकिचाहट महिलाओं में रहनेवाली है। हम हमेशा इंतजार करते हैं कि बड़ी घटनाएं होंगी, तो उसके ऊपर हमारा एक रिएक्शन होता है। छोटी-छोटी घटनाओं को दरकिनार या नजरअंदाज करके ही बड़े क्राइम को हम लोग समर्थन देते हैं। दिल्ली की सड़कों पर छेड़खानी के मामले जो हैं 116 प्रतिशत बढ़े हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ केस हुआ? वो संख्या देखिए तो बहुत कम है। जब एक महिला को

एक लड़की को कॉलेज जाते हुए छेड़ा जाता है। जब वो लड़की साहस करके कंप्लेंट करना भी चाहे तो लड़की से कहा जाता है, छेड़ा है बलात्कार तो नहीं किया, तो चुप बैठो। जब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा खुद महिलाओं को कहती हैं कि तुम्हें छेड़ते हुए कोई सेक्सी बोले तो तुम्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो हम बेटियों को किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं? कि तुम्हें कहीं न कहीं एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है और तुम्हें उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो

जब आप संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं तो एक भारतीय होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि विश्व में प्राचीन सभ्यताओं में शायद एकमात्र हमारी ही सभ्यता थी जिसने अर्द्धनारीश्वर की कल्पना की थी। शक्ति और शिव को बराबर माना जाता है आज भी। ऐसी कल्पना किसी और सभ्यता में आप नहीं देखेंगे। आप यूरोप का इतिहास पढ़ लीजिए वो आपको नहीं मिलेगा। जब मैं एक भारतीय होने के नाते अपना इतिहास देखती हूं तो जानती हूं कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का, उसमें अगर महिला का काम के माध्यम से शोषण होता है तो चाणक्य ने उसमें शोषण हेतु दण्ड भी वहां पर लिखा हुआ है।

सिस्टम से ही अलग-अलग प्रकार के आप महिला को ही कांफिडेंस नहीं दे पा रहे हैं।

दिल्ली में जो रेप की घटनाएं हुई, 2010 में तो महिला मोर्चा ने नवम्बर के माह में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखित रूप में निवेदन दिए थे कई, जिनमें से एक निवेदन ये था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहां पर आप सड़कों पर जो गाड़ियां देखते हैं, उसमें अगर काली परत फिल्म हो तो आप उस गाड़ी को रोकिए, आप वो परत निकलवाइए। आप हर माह समीक्षा कीजिए कि महिला सुरक्षा प्रदान करने में आप सक्षम हैं या आपको अपने काम को और बेहतर करने की जरूरत है। जब दिल्ली में यह घटना हुई तब मैंने सोचा कि काश किसी ने उस पत्र पर तब ध्यान दिया होता। दो साल पहले हम हमेशा घटना के बाद रिएक्ट करते हैं। घटना को रोकने के लिए कभी रिएक्ट नहीं करते और जो असामाजिक तत्व हैं उनको क्या संदेश जाता है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं, अरे, मैं तो असहाय हूं। मतलब कॉमनवेल्थ के गेम्स में घोटाला करने में असहाय नहीं हैं, सिर्फ महिला को सुरक्षा प्रदान करने में असहाय है। मुझे समझ में आता है कि अगर पार्टियां अलग-अलग हो तो अलग बात है, केन्द्र में भी वही पार्टी का राज है, प्रदेश में भी उसी पार्टी का राज है, फिर जनता की आँख में धूल झोंकने के लिए तमाशा क्यों कर रहे हैं आप? जैसा मैंने कहा न, यह सरकार घोटाले करने में कभी असहाय नहीं होती, यही सीएम घोटाले करने में बिल्कुल नम्बर वन है लेकिन सीएम पद का दुरूपयोग करना आता है, उपयोग करना नहीं आता जनता की भलाई के लिए।

दिल्ली दुष्कर्म मामले के विरोध में इंडिया गेट पर लगातार कई दिनों तक विरोध-प्रदर्शन हुआ। इसमें भाजपा महिला मोर्चा की क्या भूमिका रही?

देखिए, इंडिया गेट एक जनता का मूवमेंट था, हमारे कार्यकर्ता, हमारी आइडियोलॉजी से, हमारे संगठन से जुड़े हैं लेकिन उनकी अपनी एक स्वतंत्र सोच भी है जिसको हमने अपनी पार्टी में कभी दबाने की कोशिश नहीं की। स्वतंत्र रूप से जितने लोगों ने अपनी बात कही, जितने लोग जुड़े, वो तो हुआ ही लेकिन संगठन के मद्देनजर हमने महिला मोर्चा के माध्यम से मात्र दिल्ली में नहीं, देशभर में हमने आंदोलन किए, देशभर में हमने चर्चाएं की और जब पार्टी के माध्यम से हमने संसद के विशेष सत्र की मांग की, तो महिला मोर्चा ने हर प्रदेश में जाकर गवर्नर को ज्ञापन दिया, पार्टी के स्टैण्ड के समर्थक गए थे, ताकि देशव्यापी एक आंदोलन खड़ा हो, लेकिन सोचने की बात ये है कि हमारे पार्टी के इतिहास में पहली बार महिला की सुरक्षा का विषय लेकर कोर कमेटी की मीटिंग हुई, और किसी राजनीतिक पार्टी ने विशेष सत्र की मांग नहीं की, मांग करने वाली पहली पार्टी भाजपा थी। भाजपा ने इस विषय को सिर्फ महिला विषय सोचकर महिलाओं के सुपुर्द नहीं किया, पार्टी में पुरूष भी महिलाओं के बराबर खड़े होकर साथ बोल रहे थे कि यह सिर्फ महिलाओं की चिंता का विषय

नहीं है। पुरूषों के लिए, परिवारों के लिए भी उतना चिंता का विषय है। पार्टी की जो विकसित और आधुनिक सोच है वो जनता के सामने आई।

भाजपा का नारी-विमर्श से क्या अभिप्राय है?

जब आप संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं तो एक भारतीय होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि विश्व में प्राचीन सभ्यताओं में शायद एकमात्र हमारी ही सभ्यता थी जिसने अर्द्धनारीश्वर की कल्पना की थी। शक्ति और शिव को बराबर माना जाता है आज भी। ऐसी कल्पना किसी और सभ्यता में आप नहीं देखेंगे। आप यूरोप का इतिहास पढ़ लीजिए वो आपको नहीं मिलेगा। जब मैं एक भारतीय होने के नाते अपना इतिहास देखती हूं तो जानती हूं कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का, उसमें अगर महिला का काम के माध्यम से शोषण होता है तो चाणक्य ने उसमें शोषण हेतु दण्ड भी वहां पर लिखा हुआ है। तो एक तरफ प्राचीन भारत की सौगात है हमें और दूसरी ओर सेक्सुअल हैरेसमेंट बिल अभी तक पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ। हमारे यहां पर चन्द्रगुप्त मौर्या के जमाने में चन्द्रगुप्त की सुरक्षा के लिए महिलाओं को तैनात किया गया शस्त्रों के साथ। और आजाद भारत में हमें महिला को अधिकार सेना में मिले उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मनुस्मृति का उल्लेख बार-बार लोग करते हैं महिला को हीन दिखाने के लिए अगर कोई मनुस्मृति पढ़े तो उसमें आपको समझ में आएगा कि अगर महिला का शोषण होता है या फिर महिला के साथ दुर्व्यवहार पुरूष करता है तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें महिला पुरूष को छोड़ सकती है, ये भी लिखा है। तो मेरा ये मानना है कि कई बार मुझे लगता है कि हर देश आजकल इस खोज में रहता है कि हमारे इतिहास में ऐसा क्या था जिसको हम संजोकर रखें। या जिसके बारे में हम पूरे विश्व को बताएं और हमारे यहां पर तो इतनी प्राचीन और इतनी सुन्दर धरोहर है। लेकिन न उसके पर कोई चर्चा होती है, न उसके ऊपर कोई विश्लेषण होता है। न उसको हम ग्लोरीफाई करते हैं। मतलब यूके में, यूएस में महिला को वोट करने का अधिकार नहीं मिलता था। और हमारे देश की सभ्यता ऐसी है कि वैदिककाल में मैत्री और गार्गी जैसी विद्वान हमारे यहां थीं। प्राचीन मिथिला में शंकराचार्य और भारती के बीच शास्त्रार्थ हुआ था, तो ये हमारा इतिहास है। तो ऐसा क्यूं है कि हम अपने इतिहास से मुंह फेरते हैं। जो अच्छाइयां हैं हमारे इतिहास में, वो हम विश्व के समक्ष क्यूं नहीं रखते?

काफी लम्बे समय से महिला आरक्षण विधेयक लटका हुआ है। क्या आपको लगता है यूपीए सरकार इसे पारित करा पाएगी?

मुझे इसकी उम्मीद नहीं लगती क्योंकि इस सरकार ने महिला को सशक्त करने के लिए कोई भी ठोस कदम उठाया नहीं है। महिला का सबसे पहला सशक्तिकरण उसके अपने घर में होता है। एक महिला की आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसे दो वक्त की रोटी मिले। आज बढ़ती महंगाई में महिला दो वक्त की रोटी अपने लिए क्या, बच्चों के लिए क्या, परिवार के लिए कहां कमा पाती है? महिला की दूसरी जरूरत क्या है- स्वास्थ्य, आज सरकारी अस्पताल में या तो दवाई नहीं होती या तो डॉक्टर नहीं होता या तो इक्युप्मेंट नहीं होता। जिस देश में 50 से 60 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं या लोग ऐसे हैं जो दिन का 20 रुपए से भी कम कमाते हैं वो बीमार पड़ते होंगे तो कहां जाते होंगे? आज एजुकेशन की बात करो आप, तो हमारे देश में जो ट्राइबल लड़कियां हैं उनका ड्रापआउट रेट दसवीं के बाद 80 प्रतिशत है। दलित लड़कियों का 72 प्रतिशत है। एक महिला को पढ़ाते लिखाते क्यों नहीं, क्योंकि ब्याह करवा देना है। आज अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में 90 प्रतिशत से ज्यादा काम करने वाली महिला हैं। क्यूं? क्योंकि उसको कोई वेतन न भी दो, कुछ बेनीफीट न भी दो, चलेगा।

देखा गया है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रश्न केवल चर्चाओं तक सीमित रह जाता है। पार्टी के अंदर महिला नेतृत्व को उभारने के लिए क्या प्रयास हुए है?

मैं अपने आपको काफी सौभाग्यशाली मानती हूं कि मेरी एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसने महिला आरक्षण को पार्टी में लागू किया वो भी एक पुरूष नेता ने शुरूआत की, आडवाणी जी ने शुरूआत की, राजनाथ जी के नेतृत्व में इसको पारित किया और किसने पारित करवाया, सुषमा जी ने, जो स्वयं बिना आरक्षण के नेता बनी थी, उन्होंने अपने संघर्ष से समझा कि महिला को किस प्रकार से सहायता की जरूरत है और इस तरीके से महिला कार्यकर्ताओं को उन्होंने आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कराया। ■

सेक्युलर तंत्र पर सवाल

✍ बलबीर पुंज

भारतीय संसद पर 13 दिसंबर, 2001 को हुए आतंकी हमले की साजिश में शामिल अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा और विरोध प्रदर्शन क्या रेखांकित करता है? क्या भारत की अस्मिता और लोकतंत्र के प्रतीक पर आक्रमण करने का षड्यंत्र रचने वाले आतंकी के मानवाधिकार की चिंता होनी चाहिए? क्या निरपराधों की जान लेने वाले आतंकी की सजा माफ होने योग्य थी? कश्मीर घाटी में चार दिनों का शोक मनाने का निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि इस देश में ऐसे जिहादी तत्व भी हैं जिनका शरीर भारत में भले हो, किंतु उनका मन और आत्मा पाकिस्तान की जिहादी संस्कृति के साथ है। ऐसे ही लोगों के सहयोग से पाकिस्तान भारत को रक्तरंजित करने के अपने एजेंडे में कामयाब हो रहा है।

संसद पर हमले की साजिश पाकिस्तान पोषित लश्करे-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद द्वारा रची गई थी। जांच में जम्मू-कश्मीर के बारामूला में रहने वाले मेडिकल छात्र अफजल का नाम स्थानीय साजिशकर्ता के रूप में सामने आया। 2002 में विशेष अदालत ने अफजल को फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी मुहर लगा दी थी। उसके बाद से ही मानवाधिकारवादी संगठन और सेक्युलर दल अफजल की सजा माफ करने की मांग कर रहे थे। अफजल की पत्नी ने भी राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका भेजकर उसे माफ करने की गुहार लगाई थी। मुंबई में हुए आतंकी हमले में जिंदा पकड़े गए अजमल कसाब को फांसी दिए जाने के बाद अब अफजल को फांसी दे दी गई है, किंतु सारा घटनाक्रम कुछ गंभीर सवाल खड़े करता है। अदालत का निर्णय होने के बाद सजा देने में इतना लंबा विलंब क्यों? क्या यह वोट बैंक की राजनीति का अंग है?

जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अभी केंद्र में मंत्री गुलाम नबी आजाद ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार से अफजल की सजा माफ करने की अपील की थी। क्यों वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भय है कि अफजल की फांसी से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद एक बार फिर जिंदा हो जाएगा और राज्य व केंद्र दोनों के लिए संकट खड़ा करेगा? इसका क्या अर्थ निकाला जाए? अभी हाल ही में दिल्ली में जघन्य दुष्कर्म कांड हुआ। कल को इस कांड के आरोपियों के समर्थन में धरना-प्रदर्शन व हिंसा होने लगे तो क्या उनकी सजा लंबित कर दी जाए या उन्हें सजा से मुक्त कर दिया जाए? इस आधार पर तो जिस गुनहगार की जितनी सामर्थ्य होगी वह उतनी ही हिंसा और उपद्रव मचाकर सरकार को झुकने को मजबूर कर सकता है। ऐसे अराजक माहौल में कानून का राज और देश की सुरक्षा कैसे संभव है?

दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर 7 दिसंबर, 2011 को हुए बम धमाके की जिम्मेदारी लेते हुए 'हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी' नामक जिहादी संगठन ने मेल भेजकर यह धमकी दी थी कि अफजल की सजा माफ नहीं की गई तो ऐसे ही कई और बम धमाके होंगे। भारत को रक्तरंजित करने में जुटे पाक पोषित जिहादियों का मनोबल यदि बढ़ा है तो उसके लिए कांग्रेसनीत सत्ता अधिष्ठान की नीतियां जिम्मेदार हैं।

भारत में सेक्युलरवाद इस्लामी चरमपंथ को पोषित करने का पर्याय है।

भारतीय संसद पर 13 दिसंबर, 2001 को हुए आतंकी हमले की साजिश में शामिल अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा और विरोध प्रदर्शन क्या रेखांकित करता है? क्या भारत की अस्मिता और लोकतंत्र के प्रतीक पर आक्रमण करने का षड्यंत्र रचने वाले आतंकी के मानवाधिकार की चिंता होनी चाहिए? क्या निरपराधों की जान लेने वाले आतंकी की सजा माफ होने योग्य थी? कश्मीर घाटी में चार दिनों का शोक मनाने का निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि इस देश में ऐसे जिहादी तत्व भी हैं जिनका शरीर भारत में भले हो, किंतु उनका मन और आत्मा पाकिस्तान की जिहादी संस्कृति के साथ है। ऐसे ही लोगों के सहयोग से पाकिस्तान भारत को रक्तरंजित करने के अपने एजेंडे में कामयाब हो रहा है।

इस अवसरवादी कुत्सित मानसिकता के कारण ही असम में स्थानीय बोडो नागरिकों की पहचान व मान-सम्मान अवैध बांग्लादेशियों के हाथों रौंदा जा रहा है तो मुंबई में बांग्लादेशी और रोहयांग मुसलमानों के समर्थन में रैली निकाली जाती है। पाकिस्तानी झंडा लहराया जाता है और शहीद जवानों की स्मृति में बनाए गए अमर जवान ज्योति को तोड़ा जाता है। सेक्युलर सत्तातंत्र द्वारा मिलने वाले मानवर्द्धन का ही परिणाम है कि आतंकवादी मेल भेजकर पूरे देश को लहूलुहान करने की धमकी देते हैं। हैदराबाद में एक विधायक भड़काऊ भाषण देता है और उपस्थित हजारों की भीड़ मजहबी जुनून में राष्ट्रविरोधी नारे लगाती है, किंतु ऐसी घटनाओं पर सेक्युलर तंत्र खामोश रहता है। बहुसंख्यकों को पंथनिरपेक्षता, बहुलतावाद और प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाने वाले स्वयंभू मानवाधिकारी चुप्पी साधे रहते हैं। क्यों?

स्वयंभू मानवाधिकारियों का आरोप है कि अफजल को न्याय नहीं मिला, उसके साथ जांच एजेंसियों ने नाइंसाफी की। वामपंथी विचारधारा से प्रेरित लेखिका अरुंधती राय ने पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिख-लिख कर भारतीय कानून एवं व्यवस्था और जांच एजेंसियों को कठघरे में खड़ा किया। जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकीं महबूबा मुफ्ती एक कदम आगे हैं। पाकिस्तान की जेल में एक भारतीय नागरिक सरबजीत गलत पहचान के कारण बंद है। भारत सरकार ने उसे रिहा करने की अपील की है। महबूबा ने अफजल की तुलना सरबजीत से करते हुए केंद्र सरकार को दोहरे मापदंड नहीं अपनाने की नसीहत दे डाली थी। इन दिनों आतंकी मामलों में जेल में बंद युवा मुसलमानों को रिहा करने को लेकर सेक्युलर दलों में बड़ी बेचैनी है। हाल ही में सेक्युलर दलों के कुनबे ने प्रधानमंत्री से मिलकर इस मामले में दखल देने की अपील की थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे बंदियों को रिहा करने का वादा भी किया था। सत्ता मिलने पर सपा ने आरोपियों को रिहा करने की कवायद भी शुरू कर दी थी, किंतु अदालत ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई।

भारत पर मुसलमानों के साथ भेदभाव व उनके शोषण का आरोप समझ से परे है। पुख्ता सुबूतों और जीती-जागती तस्वीरों में कैद अजमल कसाब को मुंबई में निरपराधों की लाशें बिछाते पकड़ा गया, किंतु उसे भी पूरी निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही फांसी की सजा दी गई। इस देश में अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की कीमत पर बराबरी से अधिक अधिकार और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनके लिए अलग से आरक्षण की बात हो रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार बताते हैं। ऐसे में भेदभाव बरते जाने का आरोप निराधार है। इस देश के मुसलमान पिछड़े हैं तो इसके लिए सेक्युलर दल ही जिम्मेदार हैं, जो वोट बैंक की राजनीति के कारण उनकी मध्यकालीन मानसिकता को संरक्षण प्रदान करते हैं। अफजल को फांसी देने में हुई देरी इस कुत्सित राजनीति को ही रेखांकित करती है। ■ *(लेखक राज्यसभा सदस्य हैं)*

पृष्ठ 9 का शेष...

- विभिन्न पार्टियों के बीच बहस-मुबाहसा, चर्चाओं और आपसी विचार विमर्श के माध्यम से एक दूसरे में भरोसा पैदा करके सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दों पर राजनीतिक सकारात्मकता निर्माण करने का एक उपयुक्त तंत्र बनाना भी आवश्यक है।
- एक तंत्र का निर्माण कर राजनैतिक निहित हितों को कम से कम दखलंदाजी की अनुमति का वातावरण पैदा किया जाना चाहिए ताकि न्यायपालिका, सेना, सुरक्षा बल, गुप्तचर विभाग अपने दायित्वों को पेशेवर और यथार्थ रूप में निर्वाह करें।
- सीमा निगरानी और सुरक्षा प्रबंधन के मुद्दों को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि घुसपैठ पर कारगर ढंग से रोक लगाई जा सके। साथ ही साथ घुसपैठियों की पहचान कर उनका देश निष्कासन बिना किसी राजनीतिकरण किए किया जाना चाहिए।

इस बात पर सहमति होनी चाहिए कि जिस प्रकार का हमारा जनतांत्रिक ढांचा है, उसमें हिंसा और अलगाववाद की कोई जगह नहीं हो। कोई भी व्यक्ति या संगठन जो हिंसा और अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त पाया जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना जाएगा और उसे अपनी व्यवस्था के दायरे से बाहर माना जायेगा और साथ ही इसके लिए किसी भी प्रकार की बातचीत भी नहीं की जाएगी जब तक कि वे अपनी हिंसा और अलगाववाद का परित्याग नहीं करते हैं उन्हें तुरंत ही वर्तमान कानूनों-नियमों के अन्तर्गत दण्डित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के कड़े उपायों और राजनीतिक इच्छाशक्ति से ही राष्ट्र आतंकवादी हमलों में मारे गए पीड़ितों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकता है।

समय आ गया है कि हम चुनौती के लिए खड़े हों और आतंकवाद के खिलाफ इसे तार्किक परिणति तक पहुंचाए। ■

राजनीति में संस्कृति के राजदूत

✍ **ओमप्रकाश कोहली**

पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि फरवरी मास में पड़ती है। इस वर्ष (1913) 11 फरवरी को उनकी 45वीं पुण्यतिथि थी। उनका जन्म 25 सितम्बर 1916 को हुआ और मृत्यृ 11 फरवरी 1968 को। 25 सितम्बर 1968 को वह 52 वर्ष के होते, किन्तु लगभग सात महीने पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। हत्यारा कौन था और हत्या के पीछे उसकी मंशा क्या थी, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु भी 52 वर्ष की आयु में हुई थी। उनकी मृत्यु मृत्यु थी या षड्यन्त्र के तहत हत्या, इस पर से भी रहस्य का आवरण नहीं उतर पाया है। कैसा संयोग है कि भारतीय जनसंघ के रूप में कांग्रेस का राष्ट्रीय विकल्प खड़ा करने का चुनौतीपूर्ण काम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया तो नई गठित पार्टी को वैचारिक अधिष्ठान, दर्शन, संगठन, संविधान और सुव्यवस्थित स्वरूप देने का वैसा ही चुनौतीपूर्ण काम पं. दीनदयाल उपाध्याय ने कर दिखाया।

कुछ लोग दूर से असाधारण लगते हैं, पर जितना ही हम उनके करीब जाते हैं, उनकी असाधारणता मात्र छलावा प्रतीत होती है। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूर से सामान्य और साधारण लगते हैं, पर जितना ही उन्हें निकट से अवलोकन करते हैं, वे असाधारण दिखाई पड़ते है। दीनदयाल जी की असाधारणता उनकी साधारणता में छिपी थी। उनकी आडम्बरहीन जीवन शैली में एक मुग्धता थी।

उन्होंने आरम्भिक जीवन में अनेक आघात झेले थे। एक-के-बाद एक माता, पिता, भाई और अन्य परिजनों की मृत्यु का आघात उन्होंने झेला था, पर यह आघात शृंखला उन्हें तोड़ नहीं सकी। इन आघातों के बीच से उनका 'निर्माण' हुआ और उन्हें प्राप्त हुई वह संवदेना, वह ममता जिसके बिना मनुष्य दूसरों से जुड़ नहीं पाता।

दीनदयाल जी संघ के सम्पर्क में आए, स्वयंसेवक बने और फिर संघ के प्रचारक बने।' 1937 से 1951 तक 14 वर्ष तक वह संघ कार्य करते रहे। आगे चलकर वह 1952 से 1967 तक जनसंघ के महामंत्री के रूप में भी संघ का ही कार्य करते रहे, यद्यपि अब उनका कार्यक्षेत्र राजनीति था। राजनीति के क्षेत्र में वह संस्कृति के राजदूत थे।

दीनदयाल जी विचारक राजनेता थे, चिन्तक राजनेता थे। आज राजनीति के क्षेत्र में ऐसे राजनेताओं की बाढ़ आई हुई है जो महज नारेबाजी करते हैं, होहल्ला करते हैं, आंदोलन करते हैं, धरने-प्रदर्शन करते हैं, पर उनके पास समाज को देने के लिए न कोई विचारतत्व है न दर्शन। सत्ता हथियाने, सत्ता का सुख भोगने, जोड़-तोड़ बिठाने, आए दिन दल बदलने वाली विचारतत्व से शून्य राजनीति के स्थान पर दीनदयाल जी ने ऐसी राजनीतिक संस्कृति विकसित करनी चाही थी जिससे मनुष्य और समाज का समग्र कल्याण हो सके।

प्रचलित राजनीति से अलिप्त रहकर वह संघ के राष्ट्र निर्माण के कार्य को राजनीति के माध्यम से पूरा करने में मनोयोग से जुट गए। वह राजनीति को राष्ट्रनिर्माण का उपकरण मानते थे, लोक शिक्षण और लोक संस्कार का माध्यम मानते थे, जनसेवा और सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण का निमित्त मानते थे। दीनदयाल जी ने देश को एक नया राजनीतिक मॉडल देना चाहा, ऐसा राजनीतिक मॉडल जो भारतीयता और मूल्यों पर अधिष्ठित था, जो एकात्ममानववाद के समग्र के कल्याण के दर्शन से अनुप्राणित था, जो अन्त्योदय की ममता-करूणा-संवेदना से आप्लावित था। सत्ताभिमुखी निष्करूण और निर्मम राजनीति को उन्होंने अस्वीकार किया और सेवा-समर्पण वाली करूणामूलक राजनीति को पुरस्कृत किया।

दीनदयाल जी विचारक राजनेता थे, चिन्तक राजनेता थे। आज राजनीति के क्षेत्र में ऐसे राजनेताओं की बाढ़ आई हुई है जो महज नारेबाजी करते हैं, होहल्ला करते हैं, आंदोलन करते हैं, धरने-प्रदर्शन करते हैं, पर उनके पास समाज को देने के लिए न कोई विचारतत्व है न दर्शन। सत्ता हथियाने, सत्ता का सुख भोगने, जोड़-तोड़ बिठाने, आए दिन दल बदलने वाली विचारतत्व से शून्य राजनीति के स्थान पर दीनदयाल जी ने ऐसी राजनीतिक संस्कृति विकसित करनी चाही थी जिससे मनुष्य और समाज का समग्र कल्याण हो सके।

दीनदयाल जी ने समझाया कि राष्ट्र न केवल भूखण्ड होता है, न किसी भूखण्ड में रहने वाले मनुष्यों का समुदाय।

न किसी एक राजसत्ता द्वारा शासित और संविधान द्वारा संचालित भूखण्ड और उस पर रहने वाला समुदाय राष्ट्र कहलाता है। संविधान, शासन, भूखण्ड, जनसमुदाय, राष्ट्र का शरीर मात्र है, राष्ट्र की आत्मा तो उसकी 'चिति' है, उसका Ethos है। प्राणियों में जैसे जीन होते हैं, वैसे ही राष्ट्र का भी जीन होता है जिससे राष्ट्र स्वरूप और व्यक्तित्व ग्रहण करता है। इसे हम संस्कृति भी कह सकते हैं। संस्कृति ही राष्ट्र का प्राण तत्व है, राष्ट्र की आत्मा है, शेष सभी संघटक बाह्य शरीर मात्र है। राष्ट्र की 'चिति' को दुर्बल न होने देना, उसका निरन्तर सवंर्धन और संरक्षण करना ही राष्ट्रीयता है। जनसंघ और भाजपा की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संकल्पना दीनदयाल जी के उक्त विचारों में से उद्‌भूत हुई है।

दीनदयाल जी संगठक थे। संगठन कार्य वही कर सकता है जो अपने को पीछे रखे, न कि दूसरों को पीछे धकेल कर स्वयं आगे आने को आकुल हो। संगठन खड़ा करने के लिए कार्यकर्ता जुटाने पड़ते हैं, कार्यकर्ताओं की संभाल करनी पड़ती है, कार्यकर्ताओं से आत्मीयतापूर्ण सम्बन्ध बनाना पड़ता हैं, कार्यकर्ताओं से निरन्तर संवाद करना पड़ता है। नेता और कार्यकर्ता के बीच संवाद शिथिल पड़ने पर संगठन कमजोर हो जाता है। संगठन खड़ा करने वाले को नेतापन का अभिमान या अहंकार त्यागना होगा, अपने को सबसे आगे दिखाने का लोभ संवरण करना होगा। दीनदयाल जी से हमें संगठन शास्त्र की यह बुनियादी बात सीखनी होगी।

सार्वजनिक जीवन में प्रामाणिकता अति आवश्यक है। प्रामाणिकता हमें दूसरों का विश्वास जीतने की क्षमता और योग्यता प्रदान करती है। प्रामाणिक व्यक्ति न केवल अपनों का अपितु विरोधियों का भी विश्वास अर्जित कर लेता है। आज सार्वजनिक जीवन में प्रामाणिकता दुर्लभ वस्तु बन गई है। बनावट, चतुराई, पाखण्ड, जुगाड़, जोड़-तोड़, कथनी-करनी का अन्तर जैसी प्रवृत्तियां हावी हो गई हैं। दीनदयाल जी ने अपने जीवन और कर्तृत्व द्वारा प्रामाणिकता का जो प्रतिमान उपस्थित किया वह हमारे लिए प्रकाश स्तम्भ का काम कर सकता है। उन्होंने जौनपुर का लोकसभा चुनाव हारना स्वीकार किया, जाति की दुहाई देकर चुनावी दंगल जीतना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। दीनदयाल जी का आडम्बरहीन जीवन प्रामाणिकता की मिसाल था।

दीनदयाल जी संगठक थे। संगठन कार्य वही कर सकता है जो अपने को पीछे रखे, न कि दूसरों को पीछे धकेल कर स्वयं आगे आने को आकुल हो। संगठन खड़ा करने के लिए कार्यकर्ता जुटाने पड़ते हैं, कार्यकर्ताओं की संभाल करनी पड़ती है, कार्यकर्ताओं से आत्मीयतापूर्ण सम्बन्ध बनाना पड़ता हैं, कार्यकर्ताओं से निरन्तर संवाद करना पड़ता है। नेता और कार्यकर्ता के बीच संवाद शिथिल पड़ने पर संगठन कमजोर हो जाता है। संगठन खड़ा करने वाले को नेतापन का अभिमान या अहंकार त्यागना होगा, अपने को सबसे आगे दिखाने का लोभ संवरण करना होगा।

1967 में जनसंघ का कालीकट में अधिवेशन हुआ। दीनदयाल जी ने इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में राजनीतिक, आर्थिक और सांगठनिक अनेक विषयों पर मूल्यवान विचार व्यक्त किए। दीनदयाल जी को समझने में उनका कालीकट का अध्यक्षीय भाषण मूल्यवान दस्तावेज है। हम इस भाषण के कुछ अंशों को अविकल रूप से उद्धृत कर रहे हैं क्योंकि 45 वर्ष पूर्व व्यक्त किए गए ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। दीनदयाल जी ने कहा था :

- हमारा दल कार्यकर्ताओं का संघटन है।
- राजनीतिक चेतना को भावात्मक राष्ट्रीय अधिष्ठान पर सृजन का साधन बनाया जाना चाहिए था।
- कांग्रेस नए युग का साधन बनने में विफल रही।
- चतुर्थ आम चुनावों में कांग्रेस का अनेक प्रान्तों में पराभव हुआ।
- जनसंघ में एक विकल्प के रूप में विकसित होने के बीज विद्यमान है।

चुनाव के बाद तीन प्रकार की समस्याएं:

(क) वे प्रश्न जिनका सम्बन्ध संक्रमण काल की राजनीति से है। (विभिन्न दलों की जोड़-तोड़, दल परिवर्तन, मंत्रिमंडलों की अस्थिरता)।

(ख) वे प्रश्न जिनके बीज भारत के संवैधानिक ढांचे में हैं (केन्द्र और प्रान्तों के सम्बन्ध तथा अन्तर प्रान्तीय समस्याएं)

(ग) वे प्रश्न जो कांग्रेस की गलत एवं अयथार्थवादी नीतियों से पैदा हुए हैं (देश की अर्थव्यवस्था, गृह, सुरक्षा तथा विदेश नीति सम्बन्धी प्रश्न)

- चुनाव के बाद कुछ प्रान्तों में राज्यपालों के व्यवहार से इस पद की प्रतिष्ठा गिरी है। चुने हुए राज्यपालों की मांग उचित नहीं। इससे केन्द्रापसारी वृत्ति बढ़ेगी।
- संयुक्त मंत्रिमंडलों के गठन ने राजनीतिक छुआछूत और विलगाव की मनोवृत्ति को समाप्त करने का स्तुत्य प्रयास किया है। ''नीतिगत मतभेद रहते हुए भी दलों के बीच सहिष्णुता एवं आवश्यकतानुसार

साथ काम करने की तैयारी प्रजातंत्र का आधार तथा राष्ट्रीय एकरसता का सूचक है।''

- क्या संसदीय प्रजातंत्र का त्याग कर अध्यक्षीय प्रणाली लागू करना उचित होगा? भारत को अपनी प्रकृति के अनुरूप प्रजातंत्रीय पद्धतियों का विकास करना होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट की द्विदलीय व्यवस्था और हमारी बहुदलीय व्यवस्था।
- स्वराज्य के बाद कांग्रेस के सामने कोई निश्चित नीति एवं आदर्श नहीं रहा।
- दलों का गठन निश्चित नीति एवं सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए।
- जनता का राजनीतिक शिक्षण होने पर वह अपने मत का उपयोग दलों के कार्यक्रमों का विचार करके करेगी।
- दलबदल को कानून के बजाय जनमत और परंपरा के बल पर नियंत्रित करना होगा।
- प्रत्येक विधायक दल के अतिरिक्त अपने निर्वाचन क्षेत्र और देश के प्रति भी जिम्मेदार है।
- व्यक्ति को चुनने की ब्रिटिश पद्धति के स्थान पर दल को चुनने की पद्धति बेहतर हो सकती है। पश्चिम जर्मनी के समान दोनों पद्धतियों का समन्वय भी कर सकते हैं।
- ''संविधान का स्वरूप संघीय है किन्तु उसके प्रावधान एवं व्यवस्थाएं बहुतांश में एकात्मक है।''
- ''तनावों से देश की एकता को खतरा न पहुंचे, इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि एक ओर तो हम अपने संविधान के स्वरूप को एकात्मक बनाएं तथा दूसरी ओर प्रदेशों को दायित्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने के लिए वित्तीय स्रोतों एवं अन्य अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था करें।''

- कर जांच आयोग नियुक्त किया जाए जो आर्थिक विकास, पूंजी निर्माण, लोक कल्याण, विषमताओं में कमी तथा विकेन्द्रित प्रशासन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कर-पद्धति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन दें।
- योजना के उत्पादक परिव्यय कम कर दिये गये किन्तु शासन का अनुत्पादक खर्चा बढ़ा है।
- ''विदेशी निहित स्वार्थ आज इतने प्रबल हैं कि देश के आर्थिक कार्यक्रमों को हीं नहीं अपितु आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक क्षेत्र की नीतियों को भी प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। यदि हमें स्वतन्त्रता बचानी है तो आर्थिक क्षेत्र में स्वावलम्बी बनना होगा''।
- बिना खाद के केवल उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति पर प्रतिकूल परिणाम होगा।
- किसान को अपनी फसल के उचित और पूरे मूल्यों से वंचित रखना अन्यायपूर्ण एवं आत्मघाती होगा। मूल्य-नीति का प्रमुख उद्देश्य उत्पादकों की विशेषकर प्राथमिक उत्पादकों की आय को नीचे गिरने से बचाना होना चाहिए।
- खाद्य क्षेत्रों की नीति राष्ट्रीय एकात्मकता में बाधक है।
- देश के कामकाज के लिए अपनी ही भाषाओं का प्रयोग व्यावहारिक एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान दोनों ही दृष्टि से आवश्यक है।
- अंग्रेजी का प्रभुत्व निर्बाध बना रहे तथा हिन्दी के प्रयोग की छूट न हो, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
- समस्याओं का हौवा खड़ा करने के बजाय उन्हें हल करने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए।
- चीन ने परमाणु अस्त्रों की दिशा में काफी प्रगति की है। भारत सरकार अभी तक अपने पुराने हठवाद पर ही कायम है। हमें ये अस्त्र बनाने होंगे। बिना उनके हमारी सुरक्षा सदैव संकटापन्न रहेगी।
- जन आन्दोलन एक बदलती हुई व्यवस्था के युग में स्वाभाविक और आवश्यक है। वास्तव में वे समाज की जागृति के साधन और उसके द्योतक है। हां, यह आवश्यक है कि ये आन्दोलन दुस्साहसपूर्ण और हिंसात्मक न हों प्रत्युत वे हमारी कर्मचेतना को संगठित कर एक भावात्मक क्रान्ति का माध्यम बनें।
- ''हम अतीत के गौरव से अनुप्राणित हैं परन्तु उसको भारत के राष्ट्र जीवन का सर्वोच्च बिन्दु नहीं मानते, हम वर्तमान के प्रति यथार्थवादी हैं किन्तु उससे बंधे नहीं, हमारी आंखों में भविष्य के स्वर्णिम सपने हैं किन्तु हम निद्रालु नहीं बल्कि उन सपनों को साकार करने वाले जागरूक कर्मयोगी हैं। अनादि, अतीत, अस्थिर, वर्तमान तथा चिरन्तन भविष्य की काल जयी सनातन संस्कृति के हम पुजारी हैं।''
- हमने किसी सम्प्रदाय या वर्ग की सेवा का नहीं बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र की सेवा का व्रत लिया है। सभी देशवासी हमारे बान्धव हैं।
- हिन्द महासागर और हिमाचल से परिवेष्ठित भारत खण्ड में जब तक एकरसता, कर्मठता, समानता, सम्पन्नता, ज्ञानवता, सुख और शान्ति की सप्तजाह्नवी का पुण्य प्रवाह नहीं ला पाते हमारा भागीरथ तप पूरा नहीं होगा। ■

(लेखक भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी हैं)

"हिन्दू आतंक" का हौवा

भाजपा के तीव्र विरोध के कारण शिन्दे को मांगनी पड़ी मुआफी

✍ अम्बा चरण वशिष्ठ

जयपुर में कांग्रेस चिन्तन शिविर के समापन पर 20 जनवरी को श्री सुशील कुमार शिन्दे ने "हिन्दू आतंक" का शिगूफा छोड़ते हुये कहा था कि उनके पास एक जांच रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि चाहे वह भाजपा हो या आरएसएस उनके प्रशिक्षण शिविरों में हिन्दू आतंक को बढ़ावा दिया जाता है। हम उस पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। तब वह एक केन्द्रीय गृह मन्त्री नहीं उनके अन्दर का कांग्रेसी बोल रहा था। उस समय वह मतदाताओं के एक विशेष ग़ैर-हिन्दू वर्ग को प्रभावित व प्रलोभित करने का प्रयास कर रहे थे। उस पार्टी में जिस में कि पत्ता भी श्रीमती सोनिया गांधी व राहुल गांधी के इशारे के बिना नहीं हिलता यह नहीं हो सकता कि श्री शिन्दे उनकी मर्ज़ी के बिना अपनी जुबान भी खोलने की हिम्मत कर सकें।

जब श्री शिन्दे के इस बयान पर भाजपा ने कड़ा रूख अपनाया तो दो दिन बाद कांग्रेस यह कहने पर मजबूर हो गई कि पार्टी का मानना है कि आतंक को किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिये। उसने कहा कि श्री शिन्दे के बयान का गलत मतलब निकाला गया है। उसने कहा कि जहां तक हिन्दू या भगवा शब्द प्रयोग किये जान के सवाल है पार्टी उसका समर्थन नहीं करती।

इसी बीच श्री शिन्दे ने केन्द्रीय गृह सचिव श्री आर के सिंह को भी अपने बयान के समर्थन में घसीट लिया!

श्री शिन्दे के बहुसंख्यकों के विरुद्ध इस ग़ैर-ज़िम्मेदार वक्तव्य की सारे देश में भर्त्सना हुई। भाजपा ने सख्त रवैय्या अपनाया और निर्णय लिया कि जब तक श्री शिन्दे अपने इस कथन पर बिना शर्त मुआफी नहीं मांग लेते तब तक पार्टी उनका संसद में बहिष्कार करेगी और वह देश में जहां भी जायेंगे उनका काले झण्डे दिखा कर स्वागत करेगी।

इसी बीच विदेश मन्त्री श्री सलमान खुर्शीद भी श्री शिन्दे के समर्थन में कूद पड़े और कह दिया कि ''हिन्दू आतंक'' पर उनका कथन बिलकुल तथ्यों पर आधारित है जो जांच एजेन्सियों ने उन्हें प्रस्तुत की हैं।

श्री शिन्दे के बहुसंख्यकों के विरुद्ध इस ग़ैर-ज़िम्मेदार वक्तव्य की सारे देश में भर्त्सना हुई। भाजपा ने सख्त रवैय्या अपनाया और निर्णय लिया कि जब तक श्री शिन्दे अपने इस कथन पर बिना शर्त मुआफी नहीं मांग लेते तब तक पार्टी उनका संसद में बहिष्कार करेगी और वह देश में जहां भी जायेंगे उनका काले झण्डे दिखा कर स्वागत करेगी।

इसी बीच भाजपा ने दिल्ली समेत सारे देशभर में श्री शिन्दे के विरुद्ध जनसभायें कीं और विरोध प्रदर्शन किये जिसमें प्रमुख नेताओं के साथ-साथ हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ताओं व जनता ने भाग लिया।

अन्ततः 20 फरवरी को एक वक्तव्य जारी कर श्री शिन्दे ने जयपुर में "हिन्दू आतंक" नाम की टिप्पणी पर खेद प्रकट कर दिया और कहा कि उनके वक्तव्य का ग़लत अर्थ निकाला गया। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे वक्तव्य का अभिप्राय निकाला गया कि मैंने आतंक को किसी धर्म विशेष से सम्बन्धित किया और किन्हीं राजनीति संगठनों को इस दुष्कर्म में संलिप्त बताया। उन्होंने कहा कि उनका अभिप्राय किसी धर्म को आतंक में संलिप्त करना नहीं था और न ही किन्हीं संस्थाओं को ही जिनका उन्होंने जयपुर में नाम लिया था। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस वक्तव्य पर विवाद खड़ा हो गया था इसलिये वह यह स्पष्टीकरण पेश कर रहे हैं और उस पर खेद व्यक्त कर रहे हैं।

यह वक्तव्य देकर तो श्री शिन्दे ने जनता को यही जताने का प्रयास किया है कि जयपुर में उस दिन उन्होंने जो कहा वह उसका अर्थ नहीं समझते थे।

ख़ैर, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मन दर्शाते हुये उदारता दिखाई और श्री शिन्दे के खेद को स्वीकार कर लिया। पर साथ ही पार्टी प्रमुख प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि यदि श्री शिन्दे ने यही शालीनता पहले ही दिखा दी होती तो इस वक्तव्य का

शेष पृष्ठ 29 पर

फिर घोटाले पर घोटाला!

परंजॉय गुहा ठाकुरता

भारत में मौजूदा वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला हमें राजीव गांधी सरकार में हुए बोफोर्स तोप खरीद घोटाले की याद दिलाता है। बोफोर्स घोटाले के मामले में भी दलाली के तार इटली से ही जुड़े हुए थे। उस घोटाले की कहानी सबसे पहले स्वीडन के एक रेडियो ने उजागर की थी। उसके बाद इसकी खबरें हमारे देश के अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई।

इस घोटाले की जांच हमारे देश में काफी वक्त तक चलती रही, इसमें बार-बार एक दलाल ओट्टावियो क्वात्रोची का नाम सामने आया, वह इटली का ही था और माना जाता है, जिसके सोनिया गांधी और गांधी परिवार से नजदीकी संबंध थे। जब जांच ज्यादा तेज हुई, तो क्वात्रोची भारत से निकल भागा और फिर वापस नहीं आया। आज भी लोग समझते हैं, क्वात्रोची को सरकार की मदद से जान-बूझकर भागने दिया गया था, बाद में उसके जब्त खातों को भी खोल दिया गया। बोफोर्स का पूरा सच आज भी सामने नहीं आ सका है।

बोफोर्स घोटाले से लेकर आज तक बीते 26 साल में भारत में बहुत कुछ बदल चुका है। आज देश का आम आदमी और सिविल सोसायटी के लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं। हमारे देश और समाज में पारदर्शिता लाने का एक सक्षम हथियार मीडिया भी मजबूत हो गया है। करीब एक साल पहले अखबारों और टेलीविजन चौनलों के जरिए हेलीकॉप्टर घोटाले के बारे में खबरें सामने आई थीं। हमारी सरकार ने उस वक्त कुछ नहीं किया। रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय ने कुछ नहीं किया।

कहा गया कि यह आरोप सिर्फ अखबार की रिपोर्ट है, इसका कोई ठोस मतलब नहीं है। आज जब इटली की अदालत में आरोपियों के नाम सामने आ गए, तब दलाली की बातें सामने आ रही हैं। इटली की एक कंपनी के सीईओ जिउसेप्पे कोरसी को गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट के कागजों में सब कुछ सामने आ गया है। जिस समय यह हेलीकॉप्टर सौदा हुआ था, उस समय के भारतीय वायुसेना प्रमुख एस.पी. त्यागी इस घोटाले में निशाने पर हैं।

वे रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने सफाई दी है कि उन्होंने रिश्वत नहीं ली है। उनके रिश्तेदारों का नाम लिया जा रहा है। त्यागी ने खुद भी मान लिया है कि उनके रिश्तेदार क्या कारोबार कर रहे हैं, उन्हें उससे कोई लेना-देना नहीं है। सीबीआई जांच कर रही है। मामला उलझा हुआ लग रहा है। ...कुछ आरोपियों की ओर से कहा जा रहा है कि कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्यात किया गया, उसका पैसा मिला। कुल मिलाकर अभी तक तो अखबार में जो आया है, उससे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। आरोपी भले ही इनकार करें, लेकिन गड़बड़ी हुई है, जो साफ दिखाई पड़ रही है। सीबीआई की जांच मे क्या निकलकर आएगा, यह कहना मुश्किल है।

इस हेलीकॉप्टर दलाली घोटाले के सामने आने से दो दिन पहले ही एक चैनल ने भी दिखाया कि 2जी घोटाले में सरकारी वकील एक आरोपी के साथ सांठगांठ कर रहे थे, उन्हें यह बता रहे थे कि सीबीआई का सामना अदालत में कैसे करना है। उस सीबीआई के वकील को हटा दिया गया है, इसकी भी जांच हो रही है, यह मामला भी चर्चा में है। बहरहाल, जो हेलीकॉप्टर आने वाले थे, वो वीवीआईपी यानी अति विशिष्ट लोगों की सेवा के लिए थे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इत्यादि के लिए थे। इतने बड़े लोगों के लिए आने वाले हेलीकॉप्टरों की खरीद में भी दलाली खाई गई है, इस पर लोगों की चिंता जायज है। उधर, इटली की जिस कंपनी ने हेलीकॉप्टर बेचा है, उसने कहा कि उसके आरोपी सीईओ को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम जांच कर रहे हैं, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी। अब बजट सत्र आ रहा है, सत्ता पक्ष को समझना चाहिए कि सारे विरोधी दल संसद में बहुत शोर मचाएंगे। हंगामा

घोटाले को दबाने के लिए घोटाला हो रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाला। सरकार की छवि लगातार खराब हो रही है। कहा जाता है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भ्रष्ट नहीं हैं, लेकिन उनके रहते ए.राजा लूट ले गए। उनके रहते उनकी नाक तले कोयला घोटाला हुआ। ठीक इसी तरह से कहा जाता है कि रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी सबसे साफ-सुथरे हैं, लेकिन वे एक साल से क्या कर रहे थे? हेलीकॉप्टर सौदे पर सवाल तो पहले से ही उठ रहे थे, रक्षा मंत्री ने सच्चाई का पता लगाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया?

होगा और संसद नहीं चल पाएगी। पहले रेल बजट आएगा, फिर आम बजट आएगा... ये पारित भी होंगे, लेकिन बाकी काम बाधित हो सकता है। विरोधी दल सरकार के खिलाफ शिकायत के तमाम मुद्दे उठाएंगे। पता नहीं, आने वाले समय में सरकार क्या करेगी। सरकार कहेगी कि जांच हो रही है, जो भी दोषी हो, उसे सजा मिलेगी, लेकिन यही बातें सरकार हमेशा से कहती आ रही है और तब भी घोटाले जारी हैं।

2जी घोटाला अपने आप में बहुत गंभीर बात है। सीबीआई के सरकारी वकील एक आरोपी संजय चंद्रा की मदद करते पाए गए, तो ऐसा विपक्षियों को ही नहीं, आम लोगों को भी लगा कि सरकार के लोग अपना ही केस कमजोर कर रहे हैं और संभवत: 2जी मामले में लीपापोती हो जाएगी। यह तो घोटाले पर घोटाले वाली बात है। घोटाले को दबाने के लिए घोटाला हो रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाला। सरकार की छवि लगातार खराब हो रही है। कहा जाता है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भ्रष्ट नहीं हैं, लेकिन उनके रहते ए.राजा लूट ले गए। उनके रहते उनकी नाक तले कोयला घोटाला हुआ। ठीक इसी तरह से कहा जाता है कि रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी सबसे साफ-सुथरे हैं, लेकिन वे एक साल से क्या कर रहे थे? हेलीकॉप्टर सौदे पर सवाल तो पहले से ही उठ रहे थे, रक्षा मंत्री ने सच्चाई का पता लगाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? इटली की सरकार ने जब कार्रवाई की है, तो यहां भी मजबूरी में जांच शुरू की गई है।

रक्षा सौदे में दलाली व भ्रष्टाचार से बचने की कोशिशें जारी थीं, लेकिन उसके बावजूद एक नया घोटाला सामने आ गया। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, दोनों की ही ईमानदारी धरी रह गई। विपक्ष को यह विश्वास दिलाने में मुश्किल आएगी कि सरकार ईमानदारी से जांच करेगी। अत: यह मानकर चलिए कि संसद का आगामी सत्र मुश्किल भरा होगा। इटली की सरकार ने कार्रवाई तो की, लेकिन हम तो बोफोर्स जैसे बड़े चर्चित मामले में भी अपना पक्ष आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए हैं? ■

(राजस्थान पत्रिका से साभार)

पृष्ठ 13 का शेष...

स्वीकार पत्र हाथ लगा। जिसमें पता चलता है कि 52 मिलियन यूरो गीडो हासचके और क्रिचियन माइकल के बीच बांटने की बात कही गयी है। बाद में माइकल अपने कमीशन में 12 मिलियन यूरो कम करने पर सहमत हो गया है। ताकि हासचके और 'दि फैमली' का भी इस हिस्से में ध्यान रखा जा सके। लेकिन सहमति पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि भारत में यह 'दी फैमिली' कौन है।

भारत की मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेसनीत संप्रग सरकार से मांग की है कि 'दि फैमिली' की पहचान को उजागर करे जिस पर 200 करोड़ रुपए का रिश्वत लेने का आरोप है। भाजपा ने कहा है कि देश इन प्रश्नों का जवाब मांगता है-

1. किसने वीवीआईपी हैलिकॉप्टर सौदे को तय किया।
2. किसने रिश्वत लिया?
3. दो जगह इटली के चार्जशीट में 'दि फैमिली' का जिक्र है। देश की जनता जानना चाहती है कि वह 'दि फैमिली' कौन है?
4. हसचके और इमार एजीएफ में क्या सम्बन्ध है।
5. आई.डी.एस इण्डिया का इस हैलिकॉप्टर घोटाला में क्या भूमिका है।
6. क्या भारत सरकार इस घोटाले के सम्बन्ध में साक्ष्य के लिए प्रार्थना पत्र निर्गत किया है।

ठीक इसी तरह का विवादित तथा घाटे का सौदा राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में किया गया था। यह सौदा भी वेस्टलैण्ड कम्पनी से हैलिकॉप्टर खरीदने के लिए किया गया था। यह हैलीकॉप्टर पवनहंस द्वारा ऑयल नेचुरल गैस एजेंसी कम्पनी के लिए 21 हैलीकॉप्टर खरीदा गया था। राजीव गांधी सरकार ने पवनहंस पर दबाव देकर यह सौदा करवाया था। यह सिविल एवियेशन का सबसे घटिया सौदा था। इन हैलीकॉप्टर्स को ओएनजीसी द्वारा तेल निकालने में मदद के लिए खरीदा गया था। कुछ ही दिन बाद पता चला यह हैलीकॉप्टर नमी में (moist) उड़ान भरने योग्य नहीं है तथा काफी तेल पीता है। जो इस हैलीकॉप्टर सौदे का पहली प्राथमिकता थी कि नमी के बावजूद उड़ान भर सके क्योंकि समुद्र के ऊपर तेल निकालने के लिए उड़ान भरना था। इस 1986 के सौदे से सरकारी खजाने को काफी हानि हुई। और उस समय वैस्टलैण्ड कम्पनी जो कि इंग्लैण्ड की थी बंद होने वाली थी बाद में इटली की फिनमेकनिका ने इसे अधिगृहीत कर लिया और इसका नाम बदलकर 'अगस्टा वैस्टलैण्ड' कर दिया। फिर भी कांग्रेस की सरकार ने जानते हुए अगस्टा वैस्टलैण्ड से सौदा किया। मनमोहन सिंह संसद में इस मुद्दे पर बहस के बहाने इस घोटाले को दबाना चाहते हैं। इस तरह के पहले हुए घोटाले से भी यह जाहिर हो गया है कि जेपीसी द्वारा जांच किया जाने का भी कोई मतलब नहीं है। ■

मध्यप्रदेश ने देश में विकास का आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया : अनंत कुमार

–संवाददाता द्वारा

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री और मध्यप्रदेश प्रभारी श्री अनंत कुमार ने कहा कि मध्यप्रदेश में सुशासन, विकास और सुधार का समन्वय हुआ है जिससे मध्यप्रदेश देश में विकास के मॉडल के रूप में ख्याति अर्जित कर रहा है। मध्यप्रदेश के साथ कांग्रेस और केन्द्र की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में पक्षपातपूर्ण दुराग्रह करते हुए प्रदेश के विकास में बाधाएं डाली है किंतु भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास में अवरोध उत्पन्न नहीं होने देगी। और हर षड्यंत्र का पर्दाफाश करेगी। प्रदेश में शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन और केन्द्र में एनडीए सरकार की स्थापना का मार्ग मध्यप्रदेश से प्रशस्त होगा।

इससे पूर्व श्री अनंत कुमार, मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, श्री नरेन्द्रसिंह तोमर, श्री प्रभात झा, श्री सुंदरलाल पटवा, श्री कैलाश जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री अरविन्द मेनन सहित वरिष्ठ नेताओं ने दीप प्रज्जवलित किया और डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री नरेन्द्रसिंह तोमर, मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने श्री अनंत कुमार का पुष्पहार से स्वागत किया। श्री शिवराजसिंह चौहान ने नरेन्द्रसिंह तोमर का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन सत्ता से सर्वोच्च है। आलोक शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। वंदे मातरम के साथ बैठक की कार्यवाही आरंभ हुई। प्रदेश मंत्री श्री तपन भौमिक ने शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और दिवंगत आत्माओं के प्रति शोक श्रद्धांजलि अर्पित की।

सत्ता सामाजिक परिवर्तन का साधन है : नरेन्द्र सिंह तोमर

प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेन्द्रसिंह तोमर ने प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के भाजपा संगठन की ओर देश के अन्य संगठन आशा भरी नजरों से देखते है। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि वे संगठन के विस्तार में सतत कार्यशील रहें और यदि कोई क्षेत्र उन्हें कमजोर दिखाई देता हैं तो वहां संगठन को सशक्त बनाने के लिए कार्य करें। पैठ बनाएं और जनता का विश्वास अर्जित करें। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला क्षेत्र में विस्तार की काफी गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि 65 वर्षो में 6 वर्ष अटलजी के नेतृत्व में भाजपा को एनडीए सरकार का नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त हुआ है और अटलजी देश में तथा दुनिया में एक स्वीकार्य नेता के रूप में आदर का पात्र है। उन जैसा सर्वस्वीकार्य नेता देश में नहीं है। स्वीकार्यता जनविश्वास अर्जित करने से मिलती है। उन्होंने हमारे लिए प्रेरणा के सूत्र दिए है जिन पर चलकर हमें स्वीकार्यता अर्जित करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से हम हर चुनौती में सफल होंगे। मंच संचालन प्रदेश महामंत्री नंदकुमारसिंह चौहान ने किया।

नदियों का पानी समुद्र में नहीं जायेगा, किसान के खेत का शृंगार करेगा : शिवराजसिंह चौहान

भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का समापन करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा से मालवा के 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करने की

योजना है। इसे पूरा कर मालवा को रेगिस्तान बनने से रोका जायेगा। मध्यप्रदेश की नदियों का जल बहकर समुद्र में नहीं जायेगा। नदी जल से खेत की प्यास बुझायी जायेगी। हर खेत को पानी और हर व्यक्ति को काम भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रतिबद्धता है, जिसे पूरा किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले पांच वर्षो में मध्यप्रदेश देश का पहले नंबर का राज्य होगा। सरकार प्रदेश की तस्वीर और जनता की तकदीर बदलकर ही दम लेगी। प्रदेश में आजादी के बाद पहली बार नहरों से टेल एंड तक पानी पहुंचा है। कांग्रेस ने 45 वर्षो में प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया था इसे बढ़ाकर हमने 24 लाख हेक्टेयर किया है और यह 25 लाख हेक्टेयर तक पहुंचने जा रहा है। प्रदेश की सिंचाई योजनाओं की सिंचाई क्षमता का लाभ पहली बार आश्वस्त हुआ है। 30 साल पुरानी अधूरी पड़ी सिचांई योजनाओं को हमने पूरा करके दिखाया है। मध्यप्रदेश में जीरो प्रतिशत ब्याज पर गत वर्ष 6 हजार करोड़ रू. कर्ज बांटा गया था इस वर्ष 10 हजार करोड़ रू. का कर्ज बांटा जायेगा। खाद का अग्रिम भंडारण कर किसानों की मांग पूरी की है और इसके एवज में राज्य सरकार 59 करोड़ रू. की राशि खुद वहन करेगी। इस वर्ष प्रदेश में 115 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जायेगा। उस पर 150 रू. बोनस के सरकार भुगतान करेगी। मध्यप्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने में राज्य सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है जिसके अच्छे परिणाम आए है और राज्य सरकार को कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मध्यप्रदेश में सुशासन का ही परिणाम है कि केन्द्र सरकार को विवश होकर मध्यप्रदेश को सम्मानित करना पड़ रहा है।

उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे मध्यप्रदेश के संदर्भ में वर्ष 2003 की जमीनी वास्तविकता और पिछले 9 वर्षो में प्रदेश में हुई ऐतिहासिक प्रगति उपलब्धियों से जन जन को अवगत कराए। 45 वर्षो में जहां प्रदेश में 44 हजार कि.मी. लंबी सड़कें बनी थी अब तक हमने 80 हजार कि.मी. लंबी सड़के बनाकर गांवों को सड़को से जोडने का उपक्रम आरंभ किया है और हमारा लक्ष्य किसानो के खेत खलिहान को पक्की सडक से जोडने और विपणन के लिए समुचित संसाधन जुटाना है।

पारित प्रस्ताव के मुख्यांश

कृषि प्रस्ताव

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह ने कृषि प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वरिष्ठ नेता और सांसद श्री गणेश सिंह और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीलाल गुर्जर ने उसका समर्थन करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाकर देश की कृषि राजधानी के रूप में संवारा है। इसी तरह देश को विश्व की कृषि राजधानी बनाया जा सकेगा। प्रस्ताव में कृषि के प्रति केन्द्र सरकार की उदासीनता की निंदा की गयी और कहा गया कि केन्द्र सरकार जब तक कृषि को विकास का आधार मानकर अपनी नीतियों में संशोधन नहीं करती देश आर्थिक विकास के मामले में पिछड़ा ही रहेगा।

युवा प्रस्ताव

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री विश्वास सारंग ने प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के अवसर पर युवा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है कि मध्यप्रदेश में युवकों के लिए बढाए गए शिक्षा के अवसर नए नए टेक्नीकल कॉलेज, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, आईटीआई, इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया और कहा गया कि कृषि और उद्योगों के रोजगार के अवसर तलाशने के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने उद्योगपतियों और निवेशकों से जो अनुबंध किए है उनसे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में नया उत्साह जगा है।

राजनैतिक प्रस्ताव

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति बैठक में सर्वानुमति से राजनैतिक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कांग्रेसनीत यूपीए सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति करने की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि जिस तरह गृहमंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने भाजपा, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ पर भगवा आतंकवाद फैलाने व आतंकवादी शिविर चलाने का आरोप लगाया है यह घोर निंदनीय और आपत्तिजनक है। दरअसल यह वोटों की राजनीति का हिस्सा है। प्रस्ताव का समर्थन प्रदेश महामंत्री विनोद गोटिया, लालसिंह आर्य सहित प्रदेश कार्यसमिति के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सत्यनारायण जटिया और विक्रम वर्मा ने भी किया।

प्रस्ताव में आगे कहा गया कि यूपीए सरकार जहां सभी मोर्चो पर विफल है, विदेशों में प्रधानमंत्री की अंडर अचीवर की छवि बनी हैं, वहीं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री को सुशासन के लिए यूएन पब्लिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। ■

पृष्ठ 14 का शेष...

होती लगती है। प्रधान मन्त्री डा0 मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार को निर्दोष बताने के लिये बड़ी शेखी बघारी है कि सरकार इस मामले पर सदन में चर्चा के लिये तैयार है।

संसदीय कार्य मन्त्री तो एक कदम और आगे चले गये हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार इस मामले की जांच के लिये संयुक्त संसदीय कमेटी बनाने के लिये भी तैयार है। मन्शा साफ है। सरकार जांच न करवा कर इस मामले को लटकाना चाहती है। संयुक्त संसदीय समितियां चाहे बोफोर्स मामले में हो या पिछले वर्ष बनाई गई 2जी स्पैक्ट्रम पर, अभी तक कुछ नहीं कर सकी है। इसी बीच 13 मास बाद लोक सभा चुनाव आ जायेंगे और बात आई-गई हो जायेगी। इस प्रकार कांग्रेस की चाल काम कर जायेगी। वह चुनाव में कह सकेगी कि हमें दोषी नहीं पाया गया है।

आवश्यकता है तो बस एक एसआईटी गठित करने की जो उच्चतम न्यायालाय की निगरानी में निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को सज़ा दिलाये। यही मांग भाजपा कर रही है। ■

(लेखक भाजपा साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं)

पृष्ठ 15 का शेष...

की तेजी दिखाई, उससे एक दूसरे राजनीतिक पहलू का संकेत भी मिलता है। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता से सीधे ताल्लुक रखता है। दरअसल, कांग्रेस पार्टी और सरकार में शामिल लोग नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता और तेजी से बढ़ रहे उनके कद के सामने हड़बड़ा गए हैं। हिंदू मतदाताओं को झांसे में लेने के लिए उन्हें इससे बेहतर दूसरा विकल्प नजर नहीं आया। लेकिन देश की आम जनता पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला है। लेकिन अफजल गुरु की फांसी की टाइमिंग निश्चित तौर पर कांग्रेस की इन दोनों रणनीतियों की तरफ इशारा कर रही है। वैसे इस पूरे मामले में एक और बात ध्यान देने योग्य है। कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार अफजल गुरु को फांसी पर लटकाने का श्रेय भले अपने सिर लेना चाहती है, वास्तविकता यही है कि उसने इस दिशा में कुछ भी खास नहीं किया। जब अफजल गुरु को गिरफ्तार किया गया था और जब उसे फांसी की सजा दी गई थी, तब केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्त्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। देश की आम जनता इसे भी बखूबी समझ रही है।

बहरहाल, अफजल गुरु की फांसी पर जैसी की उम्मीद थी कुछ मानवाधिकार समर्थकों ने विरोध किया है। ऐसे लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे कश्मीर के हालात अचानक से बिगड़ जाएंगे। जो लोग ये तर्क देते हैं, मैं उनमें और देशद्रोही तत्वों में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं मानता। जबकि पूरे देश ने यह देखा है कि अफजल गुरु मामले की पूरी तरह से न्यायिक जांच हुई है, उसे अदालतों में अपना पक्ष रखने का मौका मिला है। इसके खिलाफ फांसी की सजा तय होने के बाद उसकी दया याचिका पर लगातार सुनवाई होती रही है, ऐसे में यह कहना कि इस मामले में उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, ये तथ्यों से परे है।

दरअसल, हमें यह भी समझना चाहिए कि भारत की संसद पर हमला हमारी अस्मिता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला था। इस हमले में शामिल लोगों की मदद करने का आरोप सच साबित होने के बाद अफजल गुरु को फांसी नहीं देने से आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता और दुनिया भर में हमारी छवि भी कमजोर देश के तौर पर चिन्हित होती। ■

(लेखक राज्यसभा सदस्य हैं)

(दैनिक भास्कर से साभार)

पृष्ठ 24 का शेष...

पाकिस्तान स्थित आतंकी आनन्द न उठा पाते।

यदि कांग्रेस का मन साफ होता और वह अपने कथन के प्रति ईमानदार भी होती तो उसे इस वक्तव्य पर अगर-मगर नहीं करनी चाहिये थी। उसे विदेश मन्त्री श्री सलमान खुर्शीद को भी मुआफी मांगने के लिये कहना चाहिये था जिन्होंने भी श्री शिन्दे के वक्तव्य का समर्थन किया था। पर दु:ख का विषय तो यह है कि श्री शिन्दे ने गृह सचिव के ग़ैरराजनीतिक पद को भी इस राजनीतिक विवाद में घसीट लिया।

इतना सब कुछ के बाद भी कांग्रेस का मन साफ नहीं लगता। श्री शिन्दे के खेद प्रकट करने के दूसरे ही दिन 21 फरवरी को कांग्रेस प्रवक्ता श्री पी सी चाको ने अपनी खिसियानी छुपाने के लिये कह दिया कि श्री शिन्दे का बयान तथ्यों के आधार पर इस कारण यदि किसी राजनीतिक दल की भावनायें आहत हुई हैं तो हम ऐसा नहीं चाहते थे और गृह मन्त्री ने स्पष्टीकरण दे दिया। श्री चाको ने आगे कहा कि गृह मन्त्री कभी बिना तथ्यों के नहीं बोल सकते थे और न ही उन्होंने इसका खण्डन ही किया है। पर सरकार विपक्ष के साथ बातचीत के लिये ऐसी भावना पैदा कर रही थी। ■

(लेखक भाजपा साहित्य एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं)

नए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

दिल्ली

विजय गोयल बने नए अध्यक्ष

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री विजय गोयल को दिल्ली प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।

भाजपा ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने श्री गोयल को दिल्ली प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री गोयल श्री विजेन्द्र गुप्ता की जगह लेंगे, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है।

भाजपा में राष्ट्रीय महासचिव जैसी अहम जिम्मेदारी संभालने वाले श्री विजय गोयल तीन बार सांसद रह चुके हैं। राजग सरकार में राज्यमंत्री भी थे। इसके अलावा वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें असम मामलों का पार्टी प्रभारी बनाया गया था। वह हरियाणा के लिए भी पार्टी प्रभारी रह चुके हैं।

उत्तराखंड

तीरथ सिंह रावत बने नये अध्यक्ष

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष पद पर श्री तीरथ सिंह रावत को नियुक्त कर दिया। श्री रावत ने श्री बिशन सिंह चुफाल का स्थान लिया है जिनका अध्यक्ष पद का कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो गया था। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे श्री रावत नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व में बनी उत्तराखंड की अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे।

आंध्र प्रदेश

जी. किशन रेड्डी बने पुनः प्रदेश अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने भाजपा आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष श्री जी. किशन रेड्डी को दुबारा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे श्री रेड्डी वर्तमान में आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी हैं।

केरल

वी. मुरलीधरन बने दुबारा प्रदेश अध्यक्ष

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने केरल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री वी. मुरलीधरन को फिर से इस पद पर नियुक्त किया है। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री और नेहरू युवा केंद्र के महानिदेशक रहे श्री मुरलीधरन ने केरल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नाते पार्टी को मजबूत करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

हिमाचल प्रदेश

सतपाल सत्ती दुबारा बने प्रदेश अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने श्री सतपाल सत्ती को हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका प्रदेश अध्यक्ष का यह दूसरा कार्यकाल (2012-2014) है। अ.भा.वि.प. के छात्र नेता रहे श्री सत्ती वर्तमान में ऊना से विधायक हैं।■